खंड

2

विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन

इकाई 5

वैश्विक सामूहिक धरोहर और जलवायु परिवर्तन की अवधारणाएं 85

इकाई 6

सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 98

इकाई 7

विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंधः विभेदित जिम्मेदारियों का केस 113

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

इकाई 5 वैश्विक सामूहिक धरोहर और जलवायु परिवर्तन की अवधारणाएं*

इकाई की रूपरेखा

5.0 उद्देश्य

5.1 प्रस्तावना

5.2 वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा

5.3 जलवायु परिवर्तनः सामूहिक धरोहर की एक वैश्विक समस्या

5.4 सामूहिक धरोहर की त्रासदी और मानव जाति की सामूहिक विरासत

5.5 जलवायु परिवर्तन का वैश्विक शासन

5.6 निष्कर्ष

5.7 शब्दावली

5.8 संदर्भ लेख

5.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

5.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित बाते समझ सकेंगेः

- वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा;
- सामूहिक धरोहर की वैश्विक समस्या के रूप में जलवायु परिवर्तन की अवधारणा; और
- जलवायु परिवर्तन के वैश्विक शासन के समक्ष मुद्दे।

5.1 प्रस्तावना

विश्व–भर में तेजी से आर्थिक विकास के कारण वैश्विक सामूहिक धरोहर (Global Commons) में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर निष्कासन हुआ है। कई मामलों में पुनः पूर्ति करने के लिए उनकी प्राकृतिक क्षमता, निष्कासन की अपेक्षा कम है, जिस कारण उनका तेजी से रिक्तीकरण (Depletion) हो रहा है। इसलिए, वैश्विक सामूहिक धरोहर को तत्काल सुरक्षित करने की आवश्यकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ना केवल वर्तमान पीढ़ी की भलाई के लिए, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की सततता के लिए उन संसाधनो के संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की गई।

ऐतिहासिक रूप से, वैश्विक सामूहिक धरोहर के क्षेत्रों के अंतर्गत पाए जाने वाले अधिकांश संसाधनों तक पहुंच कठिन थी। इसके अतिरिक्त, उन संसाधनों की कमी भी नहीं थी। इसलिए, वैश्विक सामूहिक धरोहर मानव अतिक्रमण (Encroachment) से सुरक्षित थे। परंतु, हाल ही के दिनों में, एक तरफ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आश्चर्यजनक उन्नति हुई है; और दूसरी ओर, संसाधनों की मांग भी कई गुना बढ़ गई है। इसने विभिन्न गतिविधियों जैसे मत्स्य पालन, वैज्ञानिक अनुसंधान, पनडुब्बी केबल बिछाने आदि (Fisheries, scientific research, laying of submarine cables etc.) में वृद्धि की है (यू. एन–U.N, 2013).

* योगदानः डॉ. सुस्मिता मित्रा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली

मानवजनित (Anthropogenic) गतिविधियों में वृद्धि और ग्रीनहाउस गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के परिणाम–स्वरूप जलवायु परिवर्तन हुआ है, जो वर्तमान में दुनिया के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक माना जाता है। जलवायु परिवर्तन को प्रायः वैश्विक सामूहिक धरोहर की सबसे प्रमुख समस्या कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रासंगिक प्रश्नों में से दो मुख्य हैं:

i) स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख जिम्मेदारी कौन लेगा; और

ii) इस वैश्विक समस्या का प्रबंधन कैसे करें।

वैश्विक सामूहिक धरोहर की कुछ खास विशेषताओं के कारण, एक या कुछ राष्ट्र इसके सत्त उपयोग को नियंत्रित या सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। उस उद्देश्य के लिए वैश्विक विश्वव्यापी सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए, विशेष रूप से वैश्विक शासन के दृष्टिकोण से, वर्तमान में वैश्विक सामूहिक धरोहर अंतरराष्ट्रीय हित का केंद्र–बिंदु हैं। यह इकाई इनमें से कुछ मुद्दों पर चर्चा करती है।

यह इकाई जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का विस्तार से वर्णन करती है। यह वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा की व्याख्या करती है और यह भी विस्तार से वर्णन करती है कि जलवायु परिवर्तन जन–साधारण समुदाय की वैश्विक समस्या क्यों है? यह सामूहिक धरोहर के समुदाय के वैश्विक शासन को संभोदित करती है। यह उन दो लोकप्रिय अवधारणाओं की व्याख्या करती है, जो प्रासंगिक कानूनी प्रबंध पर प्रभुत्व रखते हैं और विकसित के रू–बरू में विकासशील देशों के परिपेक्ष्य से, उन पर होने वाले तर्क–वितर्कों की जांच करती हैं। यह इकाई सामूहिक धरोहर के सतत शासन के लिए रचना (Design) सिद्धांतों के साथ समाप्त होती है। चूँकि विश्व का भविष्य वैश्विक सामूहिक धरोहर के संयुक्त उपयोग पर निर्भर है, इसलिए इसका शासन सतत विकास प्राप्त करने के लिए तेजी से इसके अनुरूप हो रहा है।

5.2 वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवधारणा

वैश्विक सामूहिक धरोहर, संसाधनों के विशेष संदर्भ में सामूहिक धरोहर की अधिक सामान्य अवधारणा का एक पहलू है। इसलिए वैश्विक समुदाय की अवधारणा को समझने के लिए समुदाय की अवधारणा को समझना सबसे पहले अनिवार्य है। आइए, अब देखते हैं कि सामूहिक धरोहर शब्द का क्या अर्थ है:

i) सामूहिक धरोहर (Commons)

सूसन जे. बक (Susan J. Buck, 1998) ने अपनी पुस्तक ''द ग्लोबल कॉमन्सः एन इंट्रोडक्शन'' (The Global Commons: An Introduction) में दो अलग–अलग तरीकों के माध्यम से संसाधनों के प्रसंग में सामूहिक धरोहर को समझाया हैः

i) संसाधनों की दो विशेषताएंः अपवर्जन और घटाव; तथा

ii) संसाधनों, संसाधन क्षेत्रों और संपत्ति के अधिकारों की अवधारणाएं।

संसाधनों के दोगुण अपवर्जन और घटाव

अपवर्जन (Exclusion) किसी भी संसाधन का उपयोग करने से अन्यों को बाहर करने या वर्जित करने की संभावना है। उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत (निजी) स्विमिंग पूल (Swimming Pool) का उपयोग करने से लोगों को बाहर करना बहुत आसान है, लेकिन शहर में झील से या गांव के सामान्य तलाब से लोगों को बाहर करना कठिन है। घटाव (Subtractibility) एक सीमा तक किसी संसाधन का अन्य द्वारा उपयोग होता है, जो दूसरों के लिए छोड़ी गई मात्रा को कम कर देता है। उदाहरण के लिए किसी विशेष

दिन आपके लंच–बॉक्स (Lunch Box) में भोजन अत्यधिक घटने लायक होता है यदि कोई उसे छीनकर खा लेता है, तो आप खा नहीं सकते।

सामान्य पूल संसाधन वे होते हैं, जो घटाव में अधिक होते हैं, लेकिन अपवर्जन में कम होते हैं। उदाहरण के लिए, गांव के जंगल में पाए जाने वाले संसाधन सामूहिक पूल (Common Pool) संसाधन है। प्रत्येक ग्रामीण सीमित मात्रा में फल (या यहां तक कि अन्य संसाधन) इकट्ठा करने की अधिकारी हैं, इसलिए अपवर्जन कम है। लेकिन एक बार कुछ फल अन्य लोगों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं, तो वे फल दूसरे ग्रामीणों के लिए उपलब्ध नहीं होते, अर्थात वो बहुत ही कम होते हैं। इसलिए, इस मामले में गांव का जंगल (Village Forest) सामूहिक धरोहर है।

संसाधन, संसाधन क्षेत्र, संपत्ति का अधिकार

संसाधन एक ऐसी वस्तु है, जिसका उपयोग किसी भी जीवित प्राणी की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन वे हैं, जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से उपयोग के लिए निकाले जाते हैं, जैसे–हवा, पानी, लकड़ी, प्राकृतिक गैस और तेल, लोहा, कोयला आदि। संसाधन निश्चित स्थानिक स्थान संबंधित आयामों (Fixed Spatial Dimensions) में स्थित होते हैं, जिन्हें संसाधन क्षेत्र (Resource Domains) के रूप में जाना जाता है, उदाहरण के लिए, मछली महासागर संसाधन क्षेत्र में पाई जाती है। सामूहिक धरोहर केवल संसाधन क्षेत्र है, जहां सामूहिक पूल संसाधन पाए जाते हैं। सामूहिक धरोहर छोटे हो सकते हैं, जैसे मछली पकड़ने के लिए गांव का तालाब, या बहुत बड़े जैसे विशाल समुद्र या सौरमंडल।

सामूहिक पूल संसाधनों को सामूहिक संपत्ति संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है। संपत्ति, संसाधनों के संदर्भ में, अधिकारों का एक समूह (Bundle) है, जैसे कि आधिकृत किए गए संसाधनों तक पहुंच व उनका अपवर्जन, निष्कासन या विक्रय।

ii) वैश्विक सामूहिक धरोहर (Global Commons)

संपत्ति के अधिकार समुदायों के रूप में व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूहों या राष्ट्रों द्वारा भी सुरक्षित किये जा सकते हैं। बहुत बड़े समुदाय, जोकि किसी एक देश के अधिकार क्षेत्र में नही आते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय सामूहिक धरोहर या वैश्विक सामूहिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय सामूहिक धरोहर और वैश्विक सामूहिक धरोहर के बीच बहुत कम अंतर है। अंतरराष्ट्रीय सामूहिक धरोहर एक से अधिक देशों द्वारा सहभाजित हाने वाले संसाधन क्षेत्र हैं, जैसे कि भूमध्य सागर (विभिन्न देशों जैसे स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, इसराइल, मिस्र, माल्टा, और कई अन्य द्वारा सहभाजित)। दूसरी ओर, वैश्विक सामूहिक धरोहर संसाधन क्षेत्र है, जिसमें सभी देशों की यथा बाहय (Outer Space) पर कानूनी पहुंच होती है, इसलिए बक (Buck, *op.cit.*) के अनुसार, दोनों के बीच का अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सामूहिक धरोहर अपवर्जित (कुछ देशों के लिए) है, जबकि वैश्विक सामूहिक धरोहर ऐसी नहीं हैं। पारंपरिक रूप से वैश्विक सामूहिक धरोहर को ग्रह के उन हिस्सों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है और जिनके पास सभी देशों की पहुंच है।

ऐतिहासिक रूप से, सामूहिक पूल संसाधन सरकारों और व्यक्तियों द्वारा जितना शीघ्र संभव हो निकाल (Extract) लिए जाते थे। केवल चार वैश्विक सामूहिक धरोहर मुख्य रूप से इस प्रवृत्ति के अपवाद के रूप में बने रहे है, क्योंकि उन तक पहुंचना कठिन था। इसके अतिरिक्त, उनके पास मौजूद संसाधनों का मूल्य उन्हें प्राप्त करने के प्रयास को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं था। ये निम्नलिखित हैं:

i) प्रखर समुद्र / महासागर (High seas/ the oceans)

ii) अंटार्कटिका (Antarctica)

iii) वातावरण (The atmosphere); और

iv) अंतरिक्ष (The space)

हालांकि, हाल के वर्षों में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आश्चर्यजनक प्रगति हुई है, और संसाधनों की मांग में कई गुना वृद्धि हुई है। इस बदलते संदर्भ में, इन वैश्विक सामूहिक धरोहर को सुधारने के लिए प्रसंग लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। बर्लिन मे मर्केटर अनुसंधान संस्थान (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change, Berlin) वैश्विक सामूहिक धरोहर को प्राकृतिक संसाधनों के रूप में परिभाषित करता है, जिन्हें उन के सतत उपयोग के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है; जैसे–वातावरण, भूमि और वन। वास्तव में, कुछ विद्धवान वैश्विक सामूहिक धरोहर को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं, जिनमें शिक्षा, विज्ञान, सूचना और शांति सम्मिलित है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय कानून केवल उपर्युक्त चार प्रकार के समुदायों की पहचान वैश्विक समुदाय के रूप में करता है। (यू एन–U.N, *op.cit.*)

5.3 जलवायु परिवर्तनःसामूहिक धरोहर की एक वैश्विक समस्या

वर्तमान में विश्व के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे गंभीर पर्यावरणीय संकटो में से एक है। इस संकट के पीछे मुख्य कारण विभिन्न देशों द्वारा ग्रीनहाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन है। जलवायु परिवर्तन का संयुक्त राष्ट्र ढ़ांचा सम्मेलन (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCC,1992) की तकनीकी परिभाषा के अनुसार, जलवायु परिवर्तन जलवायु के परिवर्तन को सूचित करता है, जिसके लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव गतिविधि को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो वैश्विक वातावरण की संरचना को बदल देता है, और इसके साथ ही तुलनीय समय अवधि में देखी गई अवलोकित प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता (Variability) है। सरल शब्दों में, जलवायु परिवर्तन मौसम के स्वरूप की एक लंबी अवधि (30 वर्ष से अधिक) की प्रवृत्ति को सूचित करता है।

जलवायु परिवर्तन को प्रायः निम्नलिखित कारणों से सामूहिक धरोहर की वैश्विक समस्या माना जाता हैः

- ग्रीनहाउस गैसों के लिए वायुमंडलीय कुंड (Sink) को मत्स्य की तरह एक सामूहिक पूल संसाधन के रूप में समझा जा सकता है हालांकि, मत्स्य पालन को आसानी से समुदाय (जो संसाधन के रूप में मछली प्रदान करता है) के रूप में समझा जा सकता है, वैश्विक समुदाय का वातावरण थोड़ा अलग प्रकार का है। वातावरण में पाया जाने वाला संसाधन स्वच्छ वायु है। यद्यपि इसे निकाला नहीं जाता, यह प्रदूषण के संकलित होने से दुर्लभ हो जाती है।
- किसी क्षेत्र या किसी भी राष्ट्र को वायुमंडलीय अवशोषण क्षमता (Atmospheric Absorptive Capacity) की पहुंच से पृथक करना मुश्किल या लगभग असंभव है।
- कुण्ड सेवाओं के रूप में वातावरण, विरोधी या घटने योग्य हैं, क्योंकि एक उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग की जाने वाली एक इकाई दूसरे के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि कार्बन उत्सर्जन (Carbon Emissions) को हवा में कार्बन अवशोषण क्षमता के उपयोग के रूप में देखा जाता है, तो एक देश के उत्सर्जन में अन्य देशों के लिए उपलब्ध अवशोषण क्षमता कम हो जाती है।

वातावरण में, विभिन्न देशों द्वारा वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों का अत्यधिक उत्सर्जन हो रहा है। यह वातावरण की प्राकृतिक कुंड क्षमता से बाहर चला गया है, जो जलवायु

परिवर्तन का कारण बन रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय वैश्विक सामूहिक धरोहर से वायुमंडल में संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को स्वीकार करता है। लेकिन नियमन को लेकर मतभेद है। हम इन पहलुओं पर अगले उप–भाग में चर्चा करेंगे।

बोध प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. 'वैश्विक सामूहिक धरोहर का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

2. जलवायु परिवर्तन वैश्विक सामूहिक धरोहर की समस्या क्यों है ?

....

....

....

....

5.4 सामूहिक धरोहर की त्रासदी और मानव जाति की सामूहिक विरासत

सामूहिक धरोहर की त्रासदी और मानव जाति की सामूहिक विरासत में दो लोकप्रिय अवधारणाएं हैं, जो वैश्विक समुदाय को नियंत्रित करने के लिए कानूनी लेख से प्रबल होती हैं (रंगनाथन–Ranganathan, 2016)। हालांकि, दोनों अवधारणाएं सामूहिक संसाधनों को साझा करने और संरक्षण करने की ओर ध्यान देती है, लेकिन इन दोनों धारणाओं में अंतर है। आइए हम दोनों अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं, और उनके आसपास के वातावरण पर तर्क–वितर्क करके उनकी चर्चा करते हैं:

सामूहिक धरोहर की त्रासदी (Tragedy of the Commons -ToC)

जीव विज्ञानी गैरेट हार्डिन (Garrett Hardin, 1968) के अनुसार, मानव चोरों का वंशज है, जिसका कारण सामूहिक धरोहर का अत्यधिक शोषण होता है। उनके अनुसार, अनियंत्रित सहभाजित संसाधन का प्रायः अत्यधिक शोषण होता है, क्योंकि व्यक्तिगत उपयोग कर्ताओं की रुचि अब अल्पकालिक उपयोग को अधिकतम करने की होती है। हार्डिन ने सामान्य चरागाहो के विनाश के मामले से समझाया है, क्योंकि चरवाहों ने उन पर चरने वाले मवेशियों में वृद्धि की है। उन्होंने प्रदूषण का उदाहरण भी दिया, जहां तर्क–संगत व्यक्ति को पता चलता है कि सामूहिक धरोहर में उत्सर्जन की लागत में उसका भाग इसे शुद्ध करने की लागत से बहुत कम है। इस अधिनियम के पीछे प्रलोभन (मुफ्त की सवारी–Free Rider) अर्थात बिना कुछ किए बिना अवसर का लाभ उठाना है। या दूसरों के ऊपर लागत को परिवर्तित करना है। लेकिन परिणाम–स्वरुप, यह व्यवहार प्रदूषण की एक बड़ी लागत में बढ़ोतरी करता है।

इस त्रासदी को दूर करने के लिए, हार्डिन ने सुझाव दिया कि सामूहिक धरोहर को इस में संलग्न किया जाना चाहिए और प्रवेश प्रबंधित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि या तो संसाधनों का निजीकरण किया जाए, ताकि दीर्घकालिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए

मालिक की रुचि इन संसाधनो में हो या सरकारी नियमों का नियंत्रण हो, ताकि सीमित संसाधनों का उपयोग हो। उनके अनुसार, पहुंच, पहले आओ–पहले पाओ, नीलामी, लॉटरी या धन के आधार पर हो सकती है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि इन सभी विकल्पों की अपनी सीमाएं हैं। हार्डिन ने समर्थन किया कि फिर भी समुदाय तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए एक निर्णय लिया जाना चाहिए।

मानव जाति की सामूहिक विरासत (Common Heritage of Mankind)

राजनयिक अरविद पडरो (Arvid Padro, 1967) द्वारा व्यक्त की गई मानव जाति की सामूहिक विरासत इस विचार को प्रतिबंधित करती है कि प्राकृतिक संसाधन हम सभी के हैं, न केवल इस वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी। इसलिए, हम प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में ना तो अधिकारों से वंचित हो सकते हैं न हि जिम्मेदारियों से इंकार कर सकते हैं। पडरो ने त्रासदी का एक अलग ही दृष्टिकोण अपनाया, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय के संदर्भ में। वह तकनीकी रूप से उन्नत राज्यों द्वारा समुद्र तल (विशेष रूप से भूमध्य सागर) के बारे में चिंतित थे। उन का डर यह था कि, समृद्ध देश, जिनके पास समुद्र विज्ञान पर खर्च करने के लिए संसाधन है, वे समान समुद्र से तेल, गैस और खनिजों का उपयोग कर सकते हैं। जिन गरीब देशों का भी इस समान समुद्र–तल पर अधिकार है, उन्हें इसके परिणामों को भुगतना पड़ेगा।

इन परिणामों से बचने के लिए, पडरो (*Ibid.*) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक संधि शासन (Treaty regime) की स्थापना पर सुझाव दिया। इस सिद्धांत पर कि यह मानव जाति की विरासत है, इस तरह के शासन से समुद्रतल (Seabed) का शांतिपूर्ण और क्रमबद्ध रूप से उपयोग सुनिश्चित हो सकता है। और इस प्रकार, सभी के हितों में, विशेष रूप से विकासशील राज्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है।

सामूहिक धरोहर की त्रासदी और मानव जाति की सामूहिक विरासत पर तर्क–वितर्क

यद्यपि दोनों अवधारणाएं सामान संसाधनों के संरक्षण के बारे में विचार सांझा करती है, तो भी इनके मतभेद ध्यान देने योग्य हैं, विशेष रूप से विकसित के रू–बरू विकासशील देशों की भूमिका के बारे में, जो वैश्विक सामूहिक धरोहर को सुरक्षित रखते हैं:

- सामूहिक धरोहर की त्रासदी पर आरोप है कि वह विकसित देशों के पक्ष में भेदभाव पूर्ण और पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। अंग्रेजी समुदाय के उदाहरण का हवाला देते हुए, हार्डिन (*Op.cit.*) ने सुझाव दिया है कि उन्हें संलग्न किया जाना चाहिए और प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए। हालांकि रंगनाथन (*Op.cit.*) के अनुसार, उदाहरण गलत है, क्योंकि अंग्रेजी सामूहिक धरोहर को उनके सामान्य लोगों द्वारा लंबे समय से सफलता पूर्वक प्रतिबंधित किया गया है। वास्तव में, कई अनुभव–जन्य शोधकर्ताओं ने दुनिया भर में सफल समान प्रबंधन के पर्याप्त उदाहरण दिए हैं। भारत में भी, आदिवासी लोगों को अपने सामान्य जंगलों को कुशलता से प्रबंधित करने के लिए इसी तरह का तर्क दिया जाता है।
- हार्डिन के प्रतिबंधित प्रवेश और पहुंच के सुझाव की एक और आलोचना दुनिया/विश्व में विद्यमान असमानता के परिप्रेक्ष्य से हुई है। गुप्ता (Gupta, 2019) ने तर्क दिया है कि अमीर देशों में, अमीर लोग निवेश करेंगे और सामूहिक धरोहर की पहुंच को प्रभावित करेंगे। गरीबों को हानि होगी। वास्तविक त्रासदी सामूहिक धरोहर में उपयोगिता और पहुंच में असमानता से होगी।
- पहुंच की असमानता के अतिरिक्त, वैश्विक सामूहिक धरोहर की अवनीति का प्रभाव सामाजिक न्याय से भी संबंधित है। ऐतिहासिक रूप से, विकसित देशों ने

ग्रीनहाउस गैसों (Greenhouse Gases) के अधिक उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के कारण ऊर्जा–गहन विकास पथ का अनुसरण किया है। इसी समय, विकसित देश जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों से बचने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दूसरी ओर, विकासशील देशों, विशेष रूप से कम से कम विकसित देशों, जिन्होंने जलवायु परिवर्तन में बहुत कम योगदान दिया है, वे भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए अत्यधिक असुरक्षित हैं (पावोला–Paavola, 2012).

उपरोक्त आलोचना के आलोक में, विकासशील राष्ट्रों ने वैश्विक और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए सामान विरासत के दृष्टिकोण का समर्थन किया। 1992 में UNFCC (टेलर–Taylor, 2017) की प्रस्तावना में, 'मानव जाति की सामुहिक चिंता' (Common Concern of Humankind) को 'सामुहिक विरासत' (Common Heritage) के बदले में नहीं, बल्कि उसके विकल्प के रूप में अपनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की छत्र–छाया में वैश्विक शासन व्यवस्था को भी सत्त–विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भावी पीढ़ियों के लिए वैश्विक सामूहिक धरोहर के संरक्षण को सुनिश्चित करने का समर्थन किया गया है। प्रश्न यह है कि जलवायु परिवर्तन का एक आदर्श वैश्विक शासन क्या होगा ? हम अपने अगले भाग में अब इस पर चर्चा करेंगे।

5.5 जलवायु परिवर्तन का वैश्विक शासन

जलवायु परिवर्तन के वैश्विक शासन के संबंध में, यद्यपि वातावरण कार्बन डाईओक्साइड (CO_2) और अन्य ग्रीनहाउस गैसों के लिए एक कुण्ड (Sink) के रूप में अपने कार्य में वैश्विक सामूहिक पूल संसाधन के दो मापदंडों को पूरा करता है, तब भी यह 21वीं सदी के आरंभ में सामूहिक धरोहर के रूप में शासित नहीं था (गुप्ता, 2019)। यह एक अनियमित 'शासन हीन भूमि' थी, जो यूरोपीय संघ (ई यू–E U) और कुछ अन्य देशों के अपवाद के साथ विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में सभी लोगों द्वारा स्वतंत्र रूप से सुलभ और विनियोजित थी। जिन्होंने कार्बन उत्सर्जन की कीमत चुकानी आरंभ कर दी थी।

बाद में, यह अनुभव किया गया कि वातावरण के कुशल प्रशासन के लिए विभिन्न राष्ट्रों की जलवायु नीतियों के वैश्विक सहयोग और समन्वय की आवश्यकता है। लेकिन राष्ट्रों को एक मजबूत सामूहिक कार्यवाही की समस्या (Collective Action Problem) का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि वहन या घटाव की संबंधित लागत में योगदान किए बिना एक पार्टी के घटाव से प्रत्येक व्यक्ति लाभान्वित हो सकता है, जबकि घटाव की लागत (Cost of Abatement) कम करने में अकेले घटाव करने वाला राज्य शामिल होता है। ''जलवायु परिवर्तन के शासन को कठिन बनाने वाले दो पहलू हैं:

i) वैश्विक सामूहिक धरोहर (विश्व संदर्भ में वातावरण) किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

ii) कभी–कभी वैश्विक सामूहिक धरोहर का संरक्षण और संसाधनों का सत्त उपयोग (भीतर पाए जाने वाले), राष्ट्रीय संप्रभुता और विनियम के साथ द्वंद मे रहता है। उदाहरण के लिए, कुछ देशों में जमीन के नीचे बहुत अधिक जीवाश्म ईंधन (Fossil Fuel) हो सकता है, लेकिन इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाली CO_2 के लिए निपटान स्थान वैश्विक सामूहिक धरोहर है हमारा वातावरण।

इस प्रकार हम समझते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रशासन एक जटिल मुद्दा है, जिसके सतत भविष्य के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनोर ओस्ट्रोम (Elinor Ostrom) का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सामूहिक धरोहर के अभिशासन के लिए संस्थागत विश्लेषण और विकास ढ़ांचा (Institutional Analysis and Development Framework for Governance of Commons)

शब्द 'ग्लोबल गवर्नेंस' (वैश्विक शासन) को फिंकेलस्टीन (Finkelstein,1995) द्वारा बिना प्रभुत्व प्राधिकार का शासन, राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते संबंध, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो कार्य करना, जो कार्य सरकार अपने देशों में करती है..., इस रूप में परिभाषित किया गया है। वैश्विक शासन की यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि यह लोक प्रशासन के अध्ययन के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित है।

एलिनोर ओस्ट्रोम ने अपनी पुस्तक सामूहिक धरोहर पर शासन (Governing the Commons, 1990) में ऐसे प्रश्नों को संबोधित किया है कि क्या और कैसे सामूहिक पूल (Common Pool) संसाधनों को प्रबंधित किया जाना चाहिए, ताकि अत्यधिक खपत और प्रशासनिक कठिनाइयों दोनों से बचा जा सके। उसने सामान्य पूल संसाधनों (प्रत्येक देश के भीतर स्थित) के प्रबंधन की अनेक सफलता की कहानियों को यह समझने के लिए प्रस्तुत किया कि वे वास्तविकता में कैसे शासित होते हैं।

सफलता की कहानियां यह व्यक्त करती हैं कि दोनों लोक और निजी खिलाड़ियों ने सामूहिक धरोहर के सफलता पूर्वक प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। बाहरी राजनीतिक शासन के हस्तक्षेप कुछ मामलों में ही सहायक थे। इसके अतिरिक्त कई मामलों में यह नकारात्मक रूप से भी प्रभावित हुए। इस प्रकार ओस्ट्रोम ने कई नीति विश्लेषकों के दृढ़ विश्वास/प्रतिबद्धता को चुनौती दी कि सामूहिक धरोहर की समस्याओं का केवल बाहरी अधिकारियों द्वारा प्रभावी निजी संपत्ति अधिकारों या केंद्रीकृत विनियम द्वारा ही समाधान निकाला जा सकता है।

इसके फलस्वरूप, एलिनोर ओस्ट्रोम ने छोटे पैमाने के सामूहिक पूल संसाधनों के प्रबंधन में सफल और असफल प्रयासों के उदाहरणों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के लिए संस्थागत विश्लेषण और विकास (Institutional Analysis and Development- IAD) नामक एक फ्रेमवर्क (रूपरेखा) विकसित किया है। इससे सत्त छोटे पैमाने के सामूहिक पूल संसाधन शासन के लिए फ्रेमवर्क में आठ सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार की हैः

i) उपयोगकर्ता पूल (विनियोजक) (User Pool -Appropriators) और संसाधन क्षेत्र (Resource Domain) के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमाएं होनी चाहिए।

ii) विनियोग नियम (Appropriation Rules) स्थानीय परिस्थितियों और प्रावधान नियमों (Provision Rules) (जो संसाधन रख रखाव के लिए उपयोगकर्ता आदानों को नियंत्रण करते हैं) के अनुकूल होने चाहिए। विनियोग नियम और प्रावधान नियमों को एक साथ परिचालन नियम (Operation Rules) कहा जाता है।

iii) सामूहिक विकल्प व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि संसाधन उपयोगकर्ता विनियोग और प्रावधान नियमों को स्थापित करने में भाग लेते हैं।

iv) निगरानी विनियोजकों या उनके एजेंटों द्वारा की जाती है।

v) क्रमिक (Graduated) प्रतिबंधों को विनियोजन के लिए लागू किया जाता है, जो परिचालन नियमों का उल्लंघन करते हैं।

vi) संघर्ष समाधान तंत्र सुलभ, कम कीमत पर और वैध है।

vii) शासन को व्यवस्थित करने के अधिकार बाहरी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

viii) सामूहिक पूल शासनों के लिए, जो बड़ी प्रणालियों का भाग हैः सतत उधम में स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय न्यायालयों के भीतर संस्थानों को एकत्रित करते हैं।

बक (*Op.cit.*) के अनुसार, IAD फ्रेमवर्क वैश्विक समुदाय के प्रबंधन या शासन के विश्लेषण की कुंजी बन गया है। यद्यपि सभी आठ डिजाइन सिद्धांत वैश्विक समुदाय के विश्लेषण के लिए उपयुक्त है, तो उनमें से पांच विशेष रूप से योग्य हैं:

i) स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमाएं;

ii) परिचालन नियमों और स्थानीय परिस्थितियों की अनुकूलता;

iii) निगरानी;

iv) क्रमिक विभाग; तथा

v) स्थिरतम उद्यम (Nested Enterprises)।

हालांकि, जब एलिनोर ओस्ट्रोम ने स्थानीय सामूहिक पूल संसाधनों के प्रबंधन को समझने की दिशा में बहुत प्रगति की, तो उन्होंने स्वयं सुझाव दिए कि जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौती का सामना करने के लिए वैश्विक समुदाय के शासन में अधिक शोध की आवश्यकता है। ऐसी नीति की रूपरेखा तैयार करने के लिए ओस्ट्रोम (2009) ने कई सिद्धांतों को रेखांकित किया है:

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सभी कटौतियाँ लाभदायक है, लेकिन एक भी समाधान नहीं है;
- देखा गया है कि छोटे कार्यों के महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं;
- कार्यक्रमों को परिप्रेक्ष्य के प्रति संवेदनशील होना चाहिए;
- ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण संसाधन है;
- सभी नीतियों के कई प्रभाव हैं; तथा
- वास्तविक नीतियां एक से अधिक स्तरों पर काम करती हैं; और हम काम करके सीखते हैं।

चूंकि विश्व का भविष्य वैश्विक समुदाय के संयुक्त उपयोग पर निर्भर करता है, इसलिए इसका प्रशासन सत्त विकास प्राप्त करने के लिए तेजी से प्रासंगिक हो रहा है।

बोध प्रश्न 2

नोट: i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिए गए स्थान का उपयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. दो लोकप्रिय अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए, जो वैश्विक समुदाय पर शासन करने वाले कानून लेख पर प्रभुत्व रखते हैं?

....

....

....

....

2. जलवायु परिवर्तन का प्रशासन कठिन क्यो है ?

....

....

....

....

3. एलिनोर ओस्ट्रोम द्वारा आई ए डी (IAD) फ्रेमवर्क के आठ रचनात्मक या डिजाइन सिद्धांतों की सूची बनाइए।

....

....

....

....

5.6 निष्कर्ष

ऐतिहासिक रूप से, वैश्विक सामूहिक धरोहर तक पहुंच की कमी ने इसे मानव अतिक्रमण से सुरक्षित रखा। हालांकि, तकनीकी विकास और विश्व–भर में तेजी से आर्थिक विकास, वैश्विक समुदाय में पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर उपयोग का कारण बना। इसके परिणाम–स्वरूप, उन्हीं संसाधनो के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता थी। जलवायु परिवर्तन को प्रायः वैश्विक सामूहिक धरोहर की सबसे प्रमुख समस्या कहा जाता है। हालांकि, एक या कुछ राष्ट्र स्थिति में सुधार नहीं कर सकते हैं; बल्कि विश्वव्यापी सहयोग की आवश्यकता है। इसलिए, सामूहिक धरोहर के वैश्विक प्रशासन के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हित हैं। इस इकाई में उस पर प्रकाश डाला गया है। इस इकाई ने प्रासंगिक अवधारणाओं को समझाया और विस्तृत रूप से बताया कि जलवायु परिवर्तन को प्रायः समुदाय की वैश्विक समस्या के रूप में क्यों जाना जाता है। इसने दो लोकप्रिय धारणाओं पर किए तर्क–वितर्क की जांच की है, जो विकसित के रू–बरू विकासशील देशों के दृष्टिकोण से प्रासंगिक कानूनी लेख पर प्रभुत्व रखते हैं।

इस इकाई ने नोबेल पुरस्कार विजेता एलिनोर ओस्ट्रोम के प्रासंगिक योगदानों पर भी प्रकाश डाला, जो सामान्य रूप से सामूहिक धरोहर के सतत् शासन और विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए रचनात्मक या डिज़ाइन सिद्धांत प्रदान करते हैं। यह इकाई इस तथ्य को समझने में सहायक है कि क्योंकि सतत विकास का तीसरा आयाम, अर्थात पर्यावरणीय स्थिरता, कमजोर वैश्विक शासन व्यवस्था की विशेषता है। हालांकि, जून 2012 में रियो डी जेनेरो (Rio de Janerio) में आयोजित सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, एक सुसंगत वैश्विक शासन ढांचे की कल्पना की; हालांकि, सफलता के लिए सभी देशों, बहुपक्षीय संगठनों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के बीच वैश्विक स्तर पर भागीदारी की आवश्यकता होगी। इस इकाई ने सतत विकास के व्यापक तर्क–वितर्क में कई बौद्धिक रूप–रेखाओं को जोड़ने की कोशिश की है।

5.7 शब्दावली

- **मानव जनित (Anthropogenic)**: मानव जनित शब्द मानव गतिविधि के परिणाम स्वरुप प्रभाव डालता है। कुछ मानवीय गतिविधियां पर्यावरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति पहुंचाती है, जैसा–प्रदूषण, अति उपभोग, अत्यधिक दोहन, वन रोपण आदि।
- **वायुमंडलीय कुंड (Atmospheric Sink)**: वायुमंडल के उद्भव के दौरान उसे वायुमंडलीय कुंड कहा जाता है। यह वह मार्ग है जिसके द्वारा वातावरण से गैसों को हटाया जाता है। जैविक प्रक्रिया जिनके द्वारा गैसों का वातावरण से हटाया जाता है उसे कुंड कहते है।
- **ग्रीनहाउस गैसें (Greenhouse Gases)**: वे गैसें जो थर्मल इंफ्रारेड रेंज (Thermal Infrared Range) के भीतर उज्जवल ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करती हैं।

ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाईट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन, पेरफ्लुरो कार्बन आदि है।

- **सामूहिक कार्यवाही समस्या (Collective Action Problem):** यह मूल रूप से एक सामाजिक दुविधा या ऐसी स्थिति है, जहां सभी व्यक्ति का सहयोग करना बेहतर होगा, लेकिन ऐसा करने में विफल रहते हैं, क्योंकि उन लोगों के बीच परस्पर–विरोधी हित होने के कारण वे संयुक्त कार्रवाई को निरूत्साहित करते हैं।

5.8 संदर्भ लेख

Buck, S. J. (1998). *The Global Commons: An Introduction*. Washington DC: Island Press.

Hardin, Garrett (1968). The Tragedy of the Commons. Science Vol. 162 pp: 1243–48.

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. New York: Cambridge university press.

Ostrom, E. (2009). *A Polycentric Approach for Coping with Climate Change*. The World Bank.

UN (2013). Piece, Thematic Think.*Global Governance and Governance of the Global Commons in the Global Partnership for Development beyond 2015*.Retrieved from https://www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/thinkpieces/24_thinkpiece_global_governance.pdf

Paavola, J. (2011). Climate Change: theUltimate 'Tragedy of the Commons'. Retrieved from https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pubfiles/climate-change_0.pdf

Pardo, Arvid. (1967). United Nations General Assembly Twenty-Second Session: Official Records. New York, November 1967. Retrieved from: https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/pardo_ga1967.pdf

Ranganathan, S. (2016). Global Commons. *European Journal of International Law*. *27*(3), 693-717.

Gupta, J. (2019).The Puzzle of the Global Commons or The Tragedy of Inequality: Revisiting Hardin.*Environment: Science and Policy for Sustainable Development*. 61(1),16-25.

Taylor, P. (2017). Governing the Global Commons: An Ethical-Legal Framework. *Policy Quarterly*, *13*(1).

Finkelstein, L. S. (1995). What is Global Governance. *Global Governance*. 1(3), 367-372.

5.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए:**
   - सामूहिक धरोहर केवल संसाधन क्षेत्र है, जहां सामूहिक पूल संसाधन पाए जाते हैं।
   - सामूहिक पूल संसाधन वे है, जो घटाव में उच्च है, लेकिन अपवर्जन में कम है।
   - घटाव वह सीमा है, जिसके द्वारा संसाधन का उपयोग दूसरों के लिए छोड़ी गई मात्रा को कम कर देता है।

- अपवर्जन किसी भी संसाधन का उपयोग करने से दूसरों को बाहर करने की संभावना है।
- समुदाय छोटे हो सकते हैं जैसे—मछली पकड़ने के लिए गांव का तालाब या उच्च समुद्रों या सोलर प्रणाली की तरह विशेष रूप से विशाल।

2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिएः**

- संसाधनों के मामले में संपत्ति अधिकारों का एक समूह है, जैसे कि अधिकृत किए गए संसाधनों को प्राप्त करने का अधिकार, अपवर्जन, निष्कासन, या विक्रय का अधिकार।
- संपत्ति के अधिकार व्यक्तियों, समुदायों के समूहों जैसे समुदायों या राष्ट्रों द्वारा भी धारण किए जा सकते हैं। बहुत बड़े सामूहिक धरोहर, जो किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, उन्हें अंतरराष्ट्रीय सामूहिक धरोहर या वैश्विक समुदाय कहा जाता है।
- अंतरराष्ट्रीय सामूहिक धरोहर एक से अधिक देशों द्वारा साझा किए जाने वाले संसाधन क्षेत्र हैं, लेकिन दूसरी ओर वैश्विक सामूहिक धरोहर, संसाधन क्षेत्र हैं, जिन पर सभी देशों की कानूनी पहुंच होती है।

बोध प्रश्न 2

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिएः**

- सामूहिक धरोहर की त्रासदी और मानव जाति की सामुहिक विरासत।
- सामूहिक धरोहर की त्रासदी के अनुसार, तर्कसंगत आदमी अनुभव करता है कि सामूहिक धरोहर में उसके उत्सर्जन की लागत में उसका योगदान इसे शुद्ध करने की लागत से बहुत कम है। लेकिन, यह व्यवहार, परिणाम स्वरूप, प्रदूषण की एक बड़ी लागत को जोड़ता है।
- इस समस्या को दूर करने के लिए, सामूहिक धरोहर की त्रासदी का सुझाव है कि सामूहिक धरोहर को संलग्न किया जाना चाहिए और प्रवेश प्रतिबंधित होना चाहिए।
- मानव जाति की समान विरासत के अनुसार, प्राकृतिक संसाधन हम सभी के लिए है न केवल इस वर्तमान पीढ़ी के लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है।
- समृद्ध देश जिनके पास संसाधन हैं, वे सामुहिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे गरीब देशों को सहन करना पड़ता है, जो भी सामुहिक संसाधनों पर अधिकार रखते हैं।
- इस समस्या से बचने के लिए, मानव जाति की सामूहिक विरासत सभी के हितों की रक्षा करने के लिए संधि शासन की स्थापना का सुझाव देते हैं।

2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिएः**

- सामूहिक धरोहर की त्रासदी का आरोप हैं कि विकसित देशों के पक्ष में भेदभाव—पूर्ण और पूर्वाग्रही रुख अपनाए जाते हैं। सामूहिक धरोहर की त्रासदी द्वारा सुझाए गए अंग्रेजी सामूहिक धरोहर पर प्रतिबंध लगाने पर तर्क—वितर्क किया जाता है।
- हार्डिन के प्रतिबंधित प्रवेश और प्राप्त करने के सुझाव को दुनिया में विद्यमान असमानता की पृष्ठ भूमि पर चुनौती दी गई।

- वैश्विक सामूहिक धरोहर की अद्योगति का प्रभाव भी सामाजिक न्याय से संबंधित है।
- विकासशील देश संयुक्त राष्ट्र की छत्र–छाया में मानव जाति की सामूहिक विरासत के लिए जोर दे रहे हैं।
- वैश्विक सामूहिक धरोहर (वातावरण के विशेष संदर्भ में) किसी भी देश के राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
- कभी–कभी वैश्विक समुदाय का संरक्षण और संसाधनों का स्थायी उपयोग (भीतर पाए जाने वाले), राष्ट्रीय संप्रभुता और विनियमन के साथ संघर्ष। उदाहरण के लिए कुछ देशों की जमीन में बहुत अधिक जीवाश्म ईंधन हो सकते हैं, लेकिन, इसके उपयोग से उत्पन्न होने वाली CO_2 के लिए निपटान स्थान, सीमित वैश्विक सामान वातावरण है।

3. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिएः**

- उपयोगकर्ता पूल (विनियोजक) और संसाधन क्षेत्र के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारित सीमा होनी चाहिए।
- विनियोग नियम स्थानीय परिस्थितियों और प्रावधान नियमों (जो संसाधन रख रखाव के लिए उपयोगकर्ता आदानों को विनियमित करते हैं) के अनुकूल होना चाहिए। विनियोग नियम और प्रावधान नियमों को एक साथ संचालन नियम कहा जाता है।
- सामूहिक विकल्प व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि संसाधन उपयोगकर्ता विनियोग और प्रावधान नियमों को स्थापित करने में भाग लेते हैं।
- निगरानी विनियोजकों या उनके एजेंटों द्वारा की जाती है।
- क्रमिक प्रतिबंधों को विनियोजक के लिए लागू किया जाता है, जो परिचालन नियमों का उल्लंघन करते हैं।
- संघर्ष समाधान तंत्र आसानी से उपलब्ध है, कम लागत पर है और कानूनी है।
- शासन को व्यवस्थित करने के अधिकार बारी अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त है।
- सामान्य पूल शासनों के लिए जो बड़ी प्रणालियों का भाग हैः स्थिरतम उद्यम स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय न्यायालयों के भीतर संसाधनों को एकीकृत करते हैं।
- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सभी कटौतियां लाभदायक हैं, लेकिन कोई एक समाधान नहीं है।
- कदाचित छोटे कार्यों के महत्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं। कार्यक्रमों को प्रसंग के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।
- ट्रस्ट एक महत्वपूर्ण संसाधन है।
- सभी नीतियों के अनेक प्रभाव हैं।
- वास्तविक नीतियां एक से अधिक स्तरों पर काम करती हैं, और हम काम करके सीखते हैं।

इकाई 6 सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन*

इकाई की रूपरेखा

6.0 उद्देश्य

6.1 प्रस्तावना

6.2 पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पूर्व दो दशकों की यात्रा

6.3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992

6.4 पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पश्चात् के दो दशक

6.5 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

6.6 निष्कर्ष

6.7 शब्दावली

6.8 संदर्भ लेख

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित बाते समझ सकेंगे :

- सतत् विकास पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का मार्ग प्रशस्त करने वाली आवश्यकताएं और स्थितियां;
- सतत ्विकास पर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की विशेषताएं और परिणाम; और
- अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की प्रगति।

6.1 प्रस्तावना

सतत् विकास की अवधारणा का तात्पर्य है कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा करने की योग्यता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना। इसे आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने के रूप में भी देखा जा सकता है, जो पर्यावरण के दीर्घकालिक मूल्य की रक्षा करता है (ईमास–Emas, 2015)। दुर्भाग्य से, देशों की तेज़ी से विकास दर का परिणाम यह है कि यह पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुचा चुकी है, जो एक वैश्विक सामूहिक धरोहर है। इस के सतत् उपयोग को सुनिश्चित करना एक या कुछ देशों के लिए बहुत कठिन है। इस के लिए विश्वव्यापी सहयोग की आवश्यकता है।

साथ ही, किसी को यह नहीं भूलना चाहिए कि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो विकसित देशों ने, जो ऊर्जा–गहन विकास पथ का अनुकरण करते थे, सामूहिक धरोहर को सबसे अधिक नुकसान पहुँचाया है। विकासशील देशों और विशेष रूप से सबसे कम विकसित देशों ने इस पर्यावरणीय क्षति में कम से कम योगदान दिया है। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का होना और आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के प्रभावी समाधानों का पता लगाना महत्त्वपूर्ण है।

---

* योगदानः डॉ. सुस्मिता मित्रा, सहायक प्रोफेसर, सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन शब्द से हमारा अभिप्राय विभिन्न देशों के बीच एक समझौते या संधि से है, जो सामान्य तौर पर संयुक्त राष्ट्र (UN) की छत्रछाया में होती है। आज तक, कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन विभिन्न मुद्दों या विषयों पर हुए जैसे, मानवाधिकार, शुल्क और व्यापार, तीव्र समुद्रीय लहरें, सतत् विकास और अन्य। सतत् विकास के संदर्भ में, अब तक *तीन* प्रमुख सम्मेलन हुए हैं :

1. रियो डी जेनेरो (Rio de Janeiro), ब्राजील में 1992 के पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Environment and Development-UNCED), जिसे लोक–व्यापी रूप से रियो शिखर सम्मेलन 1992 के रूप में जाना जाता है।

2. जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका (Johannesburg, South Africa) में आयोजित 2002 का सतत् विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन (World Summit on Sustainable Development-WSSO) (लोक–व्यापी रूप से रियो+10 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 2002) के रूप में जाना जाता है।

3. ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित 2012 के सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Sustainable Development–UNCSD) (लोक–व्यापी रूप से इसे रियो +20 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है)।

यह इकाई सतत् विकास पर इन तीन प्रमुख अंतरराट्रीय सम्मेलनों की प्रासंगिकता, विशेषताओं और परिणामों का उल्लेख करती है। इकाई को मोटे तौर पर चार खंडो में विभाजित किया गया है।पहला खंड रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) से पूर्व दो दशकों की यात्रा की व्याख्या करता है। दूसरा खंड शिखर सम्मेलन के प्रमुख घटको पर प्रकाश डालता है। तीसरा खंड रियो शिखर सम्मेलन अर्थात् रियो +10 और रियो +20 के पश्चात् के दशकों की यात्रा का उल्लेख करता है। इतने सारे सम्मेलनों के पश्चात् भी इतनी प्रगति प्राप्त नहीं हो सकी, इस बात का उल्लेख करते हुए इकाई खत्म होती है।

6.2 पृथ्वी शिखर सम्मेलन से पूर्व दो दशकों की यात्रा

वैश्विक जन की सुरक्षा में वैश्विक शासन की आवश्यकता की पहचान करते हुए विश्व ने 1970 के दशक के आरंभ में संयुक्त राष्ट्र की छत्रछाया के नीचे आयोजन आरंभ किया। पर्यावरणीय संबंधी प्रथम ऐतिहासिक सम्मेलन मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Human Environment) था, जो 1972 में स्टॉकहोम (Stockholm) में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में सरकारों और लोगों से विश्व भर में सभी मनुष्यों के लाभ के लिए पर्यावरण के संरक्षण के लिए साधारण प्रयासों को काम में लाने की अपील की। स्टॉकहोम सम्मेलन (1972) का प्रमुख परिणाम था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme-UNEP) की स्थापना। वैश्विक पर्यावरणीय एजेंडा स्थापित करने और वैश्विक पर्यावरण की वकालत करने के लिए यह अग्रणी वैश्विक पर्यावरणीय प्राधिकरण था। इस के साथ–साथ इसने बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों की संख्या का निर्माण किया।

संयुक्त राष्ट्र स्टॉकहोम सम्मेलन के एक दशक के पश्चात्, यह अनुभव किया गया कि न तो उत्तर में उच्च आय वाले देश हैं, और ना ही दक्षिण में कम आय वाले देश हैं, जो संसाधन आधारित आर्थिक विकास पर हार मानने को तैयार थे। आर्थिक विकास का यह रूप अस्थिरथा का प्रतीक था, क्योंकि यह प्रदूषण, एसिड (अम्लीय वर्षा–Acid Rains), वनरोपण और मरुस्थलीकरण और अन्य के बीच ओजोन परत (Ozone Layer)

के विनाश जैसे गंभीर मुद्दों के लिए प्रमुख था। इस प्रकार, विकासात्मक अवधारणा के लिए तत्काल आवश्यकता अनुभव की गई, जो पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक विकास में सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति देगी। इसलिए 1983 में यू एन के महासचिव ने नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री, ग्रो हार्लेम ब्रन्टलैंड (Gro Harlem Brundtland) को संयुक्त राष्ट्र से स्वतंत्र एक संगठन बनाने के लिए कहा, ताकि पर्यावरण और विकास संबंधी समस्याओं के साथ–साथ समाधानों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।

इस नए संगठन को ब्रन्टलैंड कमीशन (Brundtland Commission) या औपचारिक रूप से, विश्व पर्यावरण और विकास आयोग (World Council for Environment and Development-WCED) कहा जाता था। रिपोर्ट ''हमारा सामूहिक भविष्य'' (Our Common Future) जारी करने के पश्चात् 1987 में ब्रन्टलैंड आयोग आधिकारिक रूप से भंग हो गया। इस रिपोर्ट का प्रमुख महत्त्व ''सतत् विकास'' शब्द को परिभाषित करना और लोकप्रिय बनाना रहा है। हमने अपनी पिछली इकाईयों मे पढ़ा कि इसका अर्थ है वह विकास, जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भविष्यों की पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना मिलता है। इस परिभाषा मे अंतर–पीढ़ीगत समानता (Intergenerational Equity) के महत्त्व की झलक है और यह सत्त विकास को पारंपरिक पर्यावरण नीति से अलग करती है (Emas, *op.cit.*)।

ब्रन्टलैंड रिपोर्ट पर्यावरण को हानि पहुंचाएं बिना आर्थिक विकास की आवश्यकता को संबोधित करने में अपनी ओर से पहला कदम था। इस रिपोर्ट ने लोगों और संसाधनों, पर्यावरण और विकास के बीच अंतर–संबंधों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में देशों के बीच सहयोग के माध्यम से, वर्ष 2000 और उसके पश्चात् तक सतत् विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय कार्यनीतियों का सुझाव दिया।

अपनी रिर्पोट जारी करने के पश्चात्, ब्रन्टलैंड आयोग ने एक अंतरराष्ट्रीय बैठक बुलाई, जहां और अधिक ठोस पहल और लक्ष्यों की योजना बनाई जा सके। इसलिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यावरणीय अपकर्ष (Deterioration) को रोकते हुए, सामाजिक–आर्थिक विकास के प्राथमिक लक्ष्यों के साथ पर्यावरणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Environment Development-UNCED) की मांग की। अंततः UNCED 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में हुआ।

बोध प्रश्न 1

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. सतत् विकास पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

2. सतत् विकास पर हुए तीन अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों पर एक नोट लिखिए।

....

....

....

....

3. ''हमारा सामूहिक भविष्य'' रिपोर्ट के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालिए।

....

....

....

....

6.3 पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992

1992 में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो पर्यावरण व विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on Environment Development -UNCED) हुआ। इसलिए, इसे रियो शिखर सम्मेलन या रियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है, और सबसे लोकप्रिय रूप से पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। संधियों, राजनीतिक घोषणाओं और कार्य योजनाओं के रूप में विभिन्न परिणाम, बहुत महत्त्वपूर्ण रहे है (Cruickshank-क्रुकशैंक एवं अन्य, 2012)। ये निम्नलिखित हैं :

- **पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र (Rio Declaration on Environment and Development)**: पर्यावरण और विकास पर सिद्धांतों की एक राजनीतिक घोषणा।
- **एजेंडा 21 (Agenda 21)**: सतत् विकास के क्रियान्वयन के लिए खाका।
- **वन सिद्धांतों का कथन (Statement of Forest Principles)**: सिद्धांतों का गैर–अनिवार्य आधिकारिक कथन।
- **जलवायु परिवर्तन पर यू एन तंत्र सम्मेलन (UN Framework Convention on Climate Change-UNFCCC)**: एक बहुपक्षीय संधि।
- **जैविक विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity-CBD)**: एक बहुपक्षीय संधि।

पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा (Rio Declaration on Environment and Development)

यह एक राजनीतिक घोषणा थी, जिसने हमारे सबसे बड़े घर, पृथ्वी के अभिन्न और परस्पर निर्भर प्रकृति को मान्यता दी। राज्यों, प्रमुख क्षेत्रों और लोगों के बीच समान वैश्विक साझेदारी और सहयोग स्थापित करने के लिए, यह 27 सिद्धांतों के साथ आया। इन 27 सिद्धांतों में से कुछ महत्त्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित हैः

- सतत् विकास की चिंता में मानव मुख्य केंद्र है, और वे प्रकृति के साथ सामंजस्य में स्वस्थ और उत्पादक जीवन के अधिकारी है;
- सभी लोगों के लिए सतत् विकास और जीवन की उच्च्व गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए, राज्यों को उत्पादन और उपभोग के अस्थायी स्वरूप को कम और समाप्त करना चाहिए;
- विकासशील देशों की विशेष स्थिति और आवश्यकताओं को, विशेष रूप से कम से कम विकसित और उन सबसे अधिक पर्यावरण की दृष्टि से कमज़ोर को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी;
- किसी भी प्रस्तावित गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए, जिसका पर्यावरण पर महत्त्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो; और

- पर्यावरणीय प्रबंधन और विकास में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए सतत् विकास को प्राप्त करने के लिए उनकी पूर्ण भागीदारी आवश्यक है।
- स्वदेशी लोगों और उनके समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों की उनके ज्ञान और पारंपरिक प्रथाओं के कारण पर्यावरण प्रबंधन और विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्यों को अपनी पहचान, संस्कृति और हितों को पहचानना और उनका विधिवत् समर्थन करना चाहिए और सतत् विकास की उपलब्धि में उनकी प्रभावी भागीदारी को सक्षम बनाना चाहिए।

एजेंडा 21

यह मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास के संबंध में एक गैर–अनिवार्य कार्य योजना थी, जहां 21 का मतलब 21वीं शताब्दी से था अर्थात् 21वीं शताब्दी की तैयारी। इस अनुयोजन एजेंडे को विश्व भर के बहुपक्षीय संगठनों और व्यक्तिगत सरकारों द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई थी। सफल कार्यान्वयन को मुख्य रूप से सरकारों की जिम्मेदारी बनाया गया था और राष्ट्रीय कार्यनीतियों, योजनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण थे। ऐसे राष्ट्रीय प्रयासों के समर्थन और पूरक के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित था। सभी लक्ष्यों और मुद्दों को चार वर्गों के अंतर्गत रखा गया था:

भाग-I में, सामाजिक और आर्थिक आयामों को अधिकृत किया,जैसे गरीबी का सामना करना (विश्व रूप से विकासशील देशों में), उपभोग के स्वरूप को बदलना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, अधिक सतत जनसंख्या प्राप्त करना ओर निर्णय–निर्माण में सतत समाधान।

भाग-II में, विकास के लिए संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में वायुमंडलीय संरक्षण, वनों की कटाई से निपटने, कमजोर वातावरण की रक्षा, जैविक विविधता (जैव विविधता) के संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण और जैव–प्रौद्योगिकी के प्रबंधन और रेडियो एक्टिव (Radioactive) अवशेष को शामिल किया गया है।

भाग-III में, प्रमुख समूहों की भूमिका को मज़बूत करना शामिल है जैसे बच्चों और युवा, महिला, गैर–सरकारी संगठन (NGOs), स्थानीय अधिकारी, व्यापार व उद्योग कार्मिक, और स्वदेशी लोग, उनके समुदाय और किसान।

भाग-IV में विज्ञान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और वित्तीय तंत्रों जैसे कार्यान्वयन के साधनों का वर्णन किया गया है।

वन सिद्धांतों का कथन (Statement of Forest Principles)

यह सभी वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत् विकास पर वैश्विक सहमति के लिए सिद्धांतों का एक गैर–कानूनी रूप से अनिवार्य अधिकारिक वर्णन था। वन सिद्धांतों की कुछ महत्त्वपूर्ण विशिष्टताएँ हैं:

- आर्थिक विकास और जीवन के सभी रूपों के रख–रखाव के लिए वन आवश्यक हैं;
- विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों और जलवायु क्षेत्रों में, वन सिद्धांतों को सभी प्रकार के वनों (दोनों प्राकृतिक और प्रदय–Natural and Planted) पर लागू होना चाहिए;
- वर्तमान और भावी पीढ़ियों की सामाजिक, आर्थिक, पारिस्थितिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वन संसाधनों और वन भूमि को निरंतर प्रबंधित किया जाना चाहिए;
- जंगलों को वायु जनित प्रदूषण, आग, कीट और बीमारियों आदि के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए, उनके कई मूल्यों को बनाए रखने के लिए उचित उपाय किये जाने चाहिए;

- राष्ट्रीय वन नीतियों की पहचान, संस्कृति, स्वदेशी लोगों और वनवासियों के अधिकारों का विधिवत् समर्थन करना चाहिए;
- वनों के प्रबंधन, सरकार और सतत् विकास के सभी पहलुओं में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए; और
- वन संरक्षण और सतत् विकास नीतियों को आर्थिक, व्यापारिक और अन्य प्रासंगिक नीतियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र तंत्र सम्मेलन (United Nations Framework Convention on Climate Change)

यह जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान करने के लिए एक अंतर–सरकारी संधि थी, और पृथ्वी शिखर सम्मेलन (1992) में सही संकेत के लिए इसका उद्घाटन किया गया। इसने स्वीकार किया कि मानव गतिविधियों ने जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ग्रीनहाउस गैसों के वायुमंडलीय संकेंद्रण में पर्याप्त वृद्धि की है। इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि ग्रीनहाउस गैसों के ऐतिहासिक और वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन का सबसे बड़ा भाग विकसित देशों में उत्पन्न हुआ है। विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन वर्तमान में अपेक्षाकृत कम है, लेकिन वैश्विक उत्सर्जन (Global Emmissions) का भाग उनकी सामाजिक और विकास की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ेगा। इसलिए, जलवायु परिवर्तन की वैश्विक प्रकृति को सभी देशों द्वारा, उनकी सामान्य, लेकिन विभेदी जिम्मेदारियों, संबंधित क्षमताओं और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों के अनुसार, एक संभावित सहयोग की आवश्यकता होती है।

UNFCCC का उद्देश्य किसी निश्चित समय–सीमा में वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस संकेंद्रण के स्थिरीकरण को प्राप्त करना था, ताकि पारिस्थितिक तंत्र स्वाभाविक रूप से जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो सकें। यह पर्याप्त कृषि खाद्य उत्पादन और सतत् आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह कहा गया कि विकसित देशों में हितधारकों को जलवायु परिवर्तन और परिणाम स्वरूप होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए नेतृत्व करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं, विशेष रूप से जो जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति संवेदनशील हैं, उन पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। देशों को UNFCCC में पार्टियों के चार वर्गीकरण के रूप में अलग किया गया है :

i) **अनुबंधन (Annexure)-I,** 43 राष्ट्र + यूरोपीय संघ (EU): औद्योगिक देशों और अर्थ–व्यवस्थाओं में परिवर्तन काल (Economics in Transition -EIT);

ii) **अनुबंधन (Annexure)-II**, अनुबंध-I का सबसेट (Subset) है: आर्थिक सहयोग और विकास (OECD) के 24 देश + यूरोपीय संघ के सदस्य, जो EIT और विकासशील राष्ट्रों को सहायता प्रदान करेंगे; और

iii) **गैर–अनुबंधन (Non-Annexure)-I**: कम आय वाले विकासशील देश;

iv) **कम से कम विकसितदेश (Least Development Countries-LDC)**: 49 राष्ट्र जिन्हें विशेष दर्ज़ा दिया गया है।

UNFCCC का प्रमुख परिणाम क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) था। दिसंबर 1997 में, जापान के क्योटो में प्रतिनिधियों ने UNFCCC के लिए प्रोटोकॉल पर सहमति व्यक्त की, जो विकसित देशों और बाज़ार अर्थव्यवस्था के लिए परिवर्तनशील देशों को मात्रात्मक उत्सर्जन में कमी करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। विशिष्ट लक्ष्यों के साथ विभिन्न देशों में अलग–अलग क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत, अनुबंध-I पार्टियों ने 1990 और 2008–2012 के बीच (प्रथम प्रतिबद्धता अवधि)

5 प्रतिशत के औसत से नीचे छह ग्रीनहाउस गैसों (कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रो–फ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड-Carbon dioxide, Methane, Nitrous oxide, Hydro-fluorocarbons, Fluorocarbons, and Sulphur hexafluoride) के अपने समग्र उत्सर्जन को कम करने पर सहमति व्यक्त की। प्रोटोकॉल ने अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों की लागत को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए अनुलग्नक-I दलों की सहायता के लिए *तीन* लचीले तंत्र स्थापित किए :

i) उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (Emissions Trading System), जहां अनुबंध-I देश अन्य अनुबंध-I देशों से साख (Credits) खरीद सकते हैं;

ii) स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism), जहां अनुबंध-I देश गैर–अनुबंध-I देशों के हरित विकास में भाग ले सकते हैं; और

iii) संयुक्त कार्यान्वयन (Joint Implementation), जहां अनुबंध-1 अन्य अनुबंध-1 देशों में परियोजनाएं ले सकता है।

जैविक विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity-CBD)

वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के आर्थिक और सामाजिक विकास में जैविक संसाधनों का महत्त्व विश्व समुदाय द्वारा अनुभव किया गया था। इसी समय, बढ़ती मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों को खतरनाक दर से विलुप्त कर दिया गया है। इस पृष्ठ भूमि में, जैविक विविधता पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को कानूनी रूप से बाध्यकारी समुदाय की बढ़ती प्रतिबद्धता से प्रेरित, जैविक विविधता पर सम्मेलन (Convention on Biological Diversity-CBD) के तीन मुख्य उद्देश्य रहे हैः

i) जैविक विविधता का संरक्षण;

ii) जैविक विविधता के घटकों का सतत उपयोग; और

iii) आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का उचित और न्यायोचित सहभाजन।

CBD को पृथ्वी शिखर सम्मेलन, 1992 में हस्ताक्षर के लिए खोला गया और एक वर्ष पश्चात् यह प्रभावी हुआ। CBD के प्रमुख आउटपुट (Output) थे : i) कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल (Cartagena Bio Safety Protocol on Bio-Safety); ii) ऐची लक्ष्य (Aichi Targets); और iii) नागोया आनुवांशिक संसाधन प्रोटोकॉल (Nagoya Genetic Resource Protocol)।

जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था, जिसका उद्देश्य सुरक्षित संचालन, परिवहन और समकालीन संशोधित जीवों (Living Modified Organisms) के उपयोग को सुनिश्चित करना है, जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का परिणाम है और जो जैविक विविधता और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इसे 2000 में अपनाया गया था। ऐची लक्ष्य का मूलविचार, जैवविविधता के नुकसान के कारणों को संबोधित करना, सतत उपयोग को बढ़ावा देना ओर पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता आदि की कुछ अल्पावधि (2011–2020) और 2050 के लिए दीर्घ–कालिक योजनाओं द्वारा रक्षा करना है। नागोया आनुवंशिक संसाधन प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था, जिसका उद्देश्य आनुवंशिक संसाधनों (Genetic Resources) के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से सांझा करना है। यह 2014 में प्रभावी हुआ।

बोध प्रश्न 2

नोटः i) अपने उत्तर के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तर से अपना उत्तर मिलाइए।

1. 1992 में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन के परिणामों पर चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

6.4 पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पश्चात् के दो दशक

1992 पश्चात बहुत से बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते हुए। इसके बावजूद भी वैश्विक पर्यावरण को नुकसान उठाना पड़ा है। जैवविविधता का नुकसान निरंतर होता रहा है और मछली संचय (Fish Stocks) भी कम हो रहे हैं। मरुस्थलीकरण (Desertification) ने अधिक से अधिक उपजाऊ भूमि की मांग की, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव पहले से ही स्पष्ट थे, प्राकृतिक आपदाएं लगातार और अधिकतर विनाशकारी थीं और वायु, जल व समुद्री प्रदूषण ने लाखों लोगों का जीवन लेना जारी रखा। इसका एक कारण तीव्र वैश्वीकरण था। वैश्विक पर्यावरण के बिगड़ने के अतिरिक्त वैश्वीकरण ने अन्य महत्त्वपूर्ण समस्याओं जैसे अंतर और आंतर–देश की आय की असमानता को भी जन्म दिया, जिससे वैश्विक समृद्धि, सुरक्षा और सततता को बड़ा खतरा पैदा हुआ।

इन वैश्विक विषमताओं के परिप्रेक्ष्य में, विश्व में गरीबों के जीवन को मौलिक रूप से बदलने के लिए तत्काल आवश्यकता अनुभव की गई। सतत् विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन, जिसे रियो +10 भी कहा जाता है, जोहान्सबर्ग (Johannesburg) में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 10 वर्ष पश्चात् आयोजित किया गया था। इसने गरीबी उन्मूलन, बदलते उपभोग और उत्पादन स्वरूप को बदलने और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन आधार की रक्षा और प्रबंधन पर प्रकाश डाला, जो कि सतत् विकास का अनिवार्य भाग है।

जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र–बिंदु स्वच्छ पानी, स्वच्छता, पर्याप्त आश्रय, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य सुरक्षा और जैवविविधता के संरक्षण के रूप में इन बुनियादी आवश्यकताओं तक पहुँच में वृद्धि करना था। उसी समय, यह योजना बनाई गई थी कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधनों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण के बारे में अविकसितत्ा को हमेशा के लिए समाप्त करने में सहायता करेंगे।

रियो +10 का प्रमुख परिणाम जोहान्सबर्ग घोषणा थी, जो केवल विश्व नेताओं द्वारा सहमत होने के लिए एक राजनीतिक कथन के रूप में बनाई गई थी,जो सतत् विकास की दिशा में काम करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। इसने विशिष्ट समस्याओं से निपटने और औसत दर्जे के परिणामों को प्राप्त करने के लिए सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों और व्यवसायों के बीच नई साझेदारी पहल के शुभारंभ के लिए एक मंच के रूप में सेवा करने की योजना बनाई।

हालांकि, संस्थानों की बढ़ती संख्या और सतत् विकास के बारे में योजनाओं के बावजूद, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएँ तेज़ होती रहीं। 2005 के हज़ार वर्ष के पारिस्थितिकी तंत्र के आकलन के निष्कर्षों से पता चला है कि ''पिछले 50 वर्षों में, मानव इतिहास में किसी भी तुलनीय अवधि की तुलना में मनुष्यों ने पारिस्थितिकी प्रणालियों की अधिक तेज़ी से और बड़े पैमाने पर बदल दिया है, और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवन की विविधता में विशेष और व्यापक रूप से अपरिवर्तनीय नुकसान हुए हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर–सरकारी पैनल (Inter-governmental

Panel on Climate Change-IPCC) ने पता लगाया कि 1970 और 2004 के बीच वैश्विक कार्बन डाइओक्साइड CO_2 उत्सर्जन में 70 फीसदी की वृद्धि हुई है (Cruickshank *et al., op.cit.*)।

इस प्रकार, सतत् विकास के तीन आयामों : आर्थिक विकास, सामाजिक सुधार और पर्यावरण संरक्षण, के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता को फिर से प्रत्यक्ष और पुनः सक्रिय करने का अनुभव किया गया। इस पृष्ठ–भूमि में, सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो +20) 2012 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में आयोजित किया गया था। यह मूल रूप से एक 'समीक्षा' सम्मेलन की तरह था, जो 1992 से हुई प्रगति के आकलन के उद्देश्य से बना। इसलिए, इसके उद्देश्य पूर्व के दो सम्मेलनों की तुलना में बहुत सीमित थे।हालांकि, पर्यावरणीय निम्नीकरण और आय असमानता की बढ़ती चिंताओं के साथ, सतत् विकास का महत्त्व बढ़ता रहा। यह रियो +20 में भाग लेने से परिलक्षित हुआ। राज्य और सरकार के लगभग 100 प्रमुखों, कई मंत्रियों और सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के 40,000 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ, यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी सभा थी।

दोनों विषयों कोरियो +20 में प्राथमिक केंद्र–बिंदु प्राप्त हुआ : i) सतत् विकास और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था, और ii) सतत् विकास के लिए संस्थागत ढांचा। सम्मेलन का प्राथमिक परिणाम गैर–बाध्यकारी दस्तावेज "The Future We Want" (''जो भविष्य हम चाहते हैं'') था। यह 49 पृष्ठों का दस्तावेज व्यापक रूप से पूर्व कार्य योजना एजेंडा 21 के उद्देश्यों की पुष्टि करता है। इस दस्तावेज के प्रमुख केंद्र–बिंदु थे :

- हरित अर्थव्यवस्था का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा, खाद्य–सुरक्षा, सभ्य नौकरियों और अन्यों के बीच जल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके सतत् विकास को प्राप्त करने के लिए कैसे किया जा सकता है;
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme-UNEP) का सुदृढ़ीकरण;
- किसी देश की भलाई का आकलन करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product-GDP) से आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना;
- जेन्डर समानता में सुधार;
- सतत् विकास में स्वदेशी/पारम्परिक ज्ञान (Indigenous Knowledge) की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना;
- भूमि क्षरण (Land Degradation) की रोकथाम;
- स्थायी शहरों और शहरी बस्तियों की योजना बनाना;
- आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए उपकरण विकसित करना; तथा
- महासागरों और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को सुधारना और उनकी जैव–विविधता को बनाए रखना।
- एक अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दा यह है कि रियो +20 में सदस्य राज्यों ने सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) के एक संग्रह को विकसित करने, हजार वर्षों से विकास लक्ष्यों के पश्चात् 2015 में निर्माण करने और सतत् विकास के लिए एक उच्च–स्तरीय राजनीतिक मंच स्थापित करने का निर्णय लिया।

6.5 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आलोचनात्मक मूल्यांकन

1992 से, बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है और अब पर्यावरण मुद्दों पर कई सैंकड़ों अनिवार्य और गैर–अनिवार्य वैश्विक समझौते हैं, साथ ही साथ विकास के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को संबोधित करने वाले अन्य समझौतों की एक विस्तृत श्रृंखला है। इसके बावजूद, वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय समस्याएं अधिक हो गई है। प्रश्न यह उठता है कि इतने अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के पश्चात् भी इतनी प्रगति क्यों नहीं हो सकी ? इसके पीछे निम्नलिखित कुछ कारण बताए जा सकते हैं :

- अधिकांश पर्यावरणीय समस्याएं प्रकृति में वैश्विक हैं और अधिकांश राष्ट्रीय सरकारें प्रायः वैश्विक समस्याओं की अपेक्षा राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय प्राथमिकता देती हैं;
- तीव्र वैश्वीकरण ने वैश्विक पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाले, साथ ही साथ वैश्विक सतत् विकास की पूर्ण–प्राप्ति के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में अंतर और आंतर–देश की आय असमानताओं को प्रभावित किया;
- अंतरराष्ट्रीय निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है, क्योंकि किसी भी कार्रवाई को करने से पूर्व कई राष्ट्रीय सरकारों का सहमत होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक निर्णय–निर्माण स्तर पर बहुत कम लोकतांत्रिक जवाबदेही है, जिसके परिणामस्वरूप, कार्रवाई के लिए प्रभावी सार्वजनिक या लोक दबाव उत्पन्न करना कठिन है;
- संस्थागत समस्याएँ रही हैं; उदाहरण के लिए, यू एन ई पी (UNEP) को संयुक्त राष्ट्र का 'पर्यावरणीय विवेक' (Environmental Conscience) माना गया। यू एन ई पी एक विशेष एजेंसी नहीं हैं, लेकिन एक सहायक कार्यक्रम के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा से जुड़ी हुई है। यू एन ई पी के आलोचक प्रायः सुझाव देते हैं कि एक सहायक कार्यक्रम होने के कारण इसके काम के प्रभाव और प्रभावशीलता को प्रतिबंधित किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों की समान उच्चता नहीं होने के कारण, इसके लिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना अधिक कठिन हो जाता है;
- कई अलग–अलग अंतरराष्ट्रीय संगठन, कार्यक्रम और निकाय है, जो वैश्विक स्तर पर सतत् विकास को संचालित करते हैं। इन निकायों में से प्रत्येक के अपने अलग उद्देश्य और जनादेश है और इस कारण ये, कुछ हद तक, स्वायत्त रूप से कार्य कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः खंडित और खंडित प्रक्रियाएँ और समझौते होते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों को नियंत्रित करते हैं; और
- अंतिम लेकिन लघुतम नहीं, ऐतिहासिक रूप से विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों का वैश्विक सामुहिक धरोहर (Global Commons) को नुकसान पहुंचाने में अधिक योगदान था। इस प्रकार, जब तक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यू एस ए जैसे विकसित देशों से अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित नहीं करते, तब तक सफलता की संभावना बेरंग होगी।

बोध प्रश्न 3

नोटः i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन के पश्चात् की दो दशकों की यात्रा के बारे में बताइए।

....

....

....

....

2. अनगिनत अंर्तराष्ट्रीय सम्मेलनों के बावजूद सतत् विकास के क्षेत्र में प्रगति की कमी के कारणों की जांच कीजिए।

....

....

....

....

6.6 निष्कर्ष

पर्यावरण एक वैश्विक सामूहिक धरोहर हैं। इसलिए एक या कुछ देशों के लिए इसका सत्त उपयोग सुनिश्चित करना असंभव या कठिन है। उसके लिए विश्वव्यापी सहयोग की आवश्यकता है।साथ ही चूंकि यह विकसित देश थे, जिन्होनें विकासशील और कम से कम विकसित देशों की तुलना में वैश्विक सामूहिक धरोहर को अधिक नुकसान पहुँचाया है। इसलिए, एक तरफ, आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के सफल समाधानों का पता लगाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का होना महत्त्वपूर्ण है, और दूसरी तरफ इनका होना विकसित और विकासशील देशों के बीच कुछ सामान्य और कुछ विभेदित जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने के लिए है।

इस इकाई में सतत विकास पर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रभाव की चर्चा की गई है। यह प्रत्येक सम्मेलन की पृष्ठभूमि और प्रासंगिकता की व्याख्या भी करता है, और उनके प्रमुख परिणामों पर प्रकाश डालता है। इस इकाई में यह पता लगाने की कोशिश की है कि अनेक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के बाद भी इतनी प्रगति क्यों नहीं हो सकी है। संस्थागत समस्याओं के अतिरिक्त, ये सम्मेलन विकसित देशों से मज़बूत प्रतिबद्धता सुनिश्चित नहीं करवा सके। जब तक विकसित देश बड़ी भूमिका नहीं निभाते, तब तक विकासशील देशों को कम प्रोत्साहन मिलेगा।

इन सम्मेलनों के परिणाम हमेशा विकासशील देशों के पक्ष में नहीं थे, जो विकासशील देशों के दृष्टिकोण से प्रमुख चिंता का विषय है। उदाहरण के लिए, रियो +20 ने विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation-WTO) के माध्यम से राष्ट्रों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देते हुए कहा कि सतत विकास और गरीबी हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका अपने कपास और मक्का किसानों को बहुत अधिक सब्सिडी (Subsidies) देता है। इसलिए यदि यह पूर्णतया मुक्त प्रणाली है, तो यू एस ए उन उत्पादों को भारत जैसे अन्य विकासशील देशों में निर्यात कर सकता है, जहां भारतीय किसान प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

इसलिए, भारत संरक्षण को प्राथमिकता देता है और विकास को प्राप्त करने के लिए एक निष्पक्ष और न्यायसंगत वैश्विक व्यापार व्यवस्था की मांग करता है। हरित अर्थव्यवस्था के विषय में, अंधिकांश हरित पर्यावरण की अनुकूल तकनीक विकसित देशों के पास हैं। इसलिए भारत जैसे विकासशील देश चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंचों द्वारा विकसित देशों

से विकासशील देशों के लिए इन तकनीकों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि बाद में हरित अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के लिए उचित मूल्य पर विकासशील देशों को विकसित किया जा सके। संक्षेप में, दोनों के बीच कुछ सामान्य और कुछ भेदित (Differentiated) जिम्मेदारियों की अवधारणा को प्राप्त करने के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों तक संसाधनों और प्रौद्योगिकियों का पर्याप्त प्रवाह होना चाहिए।

6.7 शब्दावली

अम्लीय वर्शा (Acid Rains): इसे तेज़ाब जमाघर भी कहते है। इसमें शामिल है किसी भी प्रकार का अवशेपण जिसमें तेज़ाब जैसे पुर्ज़े हो जैसे सलफ्यूरिक या नाईट्रिक एसिड। जब सलफर डाईओक्साइड व नाइट्रोजन आक्साइड हवा में छोड़े जाते है। तब ये इतने ऊचे जाते है कि पानी व पानी के वेपर (Vapour) और दूसरे रासायनों में मिल जाते है। यही धरती पर वर्षा, धुधहिम (Fog), हिमपात व आंधी के रूप में आते हैं।

अंतर–पीढ़ीगत समानता (Intergenerational Equity): अंतर–पीढ़ीगत पीढ़ियों के बीच संबंधों और लेन देन को संदर्भित करता है। इस प्रकार अंतर–पीढ़ीगत समानता का अर्थ है पीढ़ियों के बीच निष्पक्षता या न्याय। सतत् विकास के विशेष संदर्भ में यह पीढ़ियों के उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के न्याय को संदर्भित करता है।

हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy): हरित अर्थव्यवस्था की अवधारणा अर्थशास्त्र और पारिस्थिति को जोड़ती है। एक अर्थव्यवस्था का ध्यान न केवल अंतरराष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनने के लिए होना चाहिए, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक रूप से स्वीकार्य भी होना चाहिए। हरित अर्थव्यवस्था वह है, जो सामाजिक कल्याण को बढ़ाती है, गरीबी का सामना करती है और सामाजिक न्याय के लिए प्रयास करती है।

यू एन सी ई डी (United Nations Conference on Environment and Development): इसे रियो डी जेनेरो पृथ्वी शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ये 1992 मे हुआ था।

यू एन ई पी (United Nations Environment Programme): यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र के 1972 में प्रयावर्णीय मुद्दे से जुड़ी प्रकियाओ का समन्वयन करने के लिए बना है।

6.8 संदर्भ लेख

Cruickshank, E. W., Schneeberger, K., & Smith, N. (2012).A Pocket Guide to Sustainable Development Governance. Retrieved from https://www.circleofblue.org/wp-content/uploads/2012/07/PocketGuidetoSDGEdition2webfinal%E2%80%93Stakeholder-Forum.pdf

Emas, R. (2015). *The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles*. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5839GSDR%202015_SD_concept_definiton_rev.pdf

Imperatives, S. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf

UN. (2012). The Future we Want. Retrieved from https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/66/288&Lang=E

UN. (1992). *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*. Retrieved from https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf

UN. (1992a). *Rio Declaration on Environment and Development*. Retrieved from https://www.jus.uio.no/lm/environmental.development.rio.declaration.1992/portrait.a4.pdf

UN. (1992b). *Convention on Biological Diversity*. Retrieved from https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf

UN. (2002). *Report of the World Summit on Sustainable Development*. Retrieved from https://digitallibrary.un.org/record/478154?ln=en#record-files-collapse-header

UN. (2006). *United Nations Framework Convention on Climate Change*. Retrieved fromhttp://unfccc.int/resource/docs/publications/handbook.pdf

UNCED. (1992). *Agenda 21*. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf

6.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिये:**
   - देशों की तीव्र विकास दर से पर्यावरण को गंभीर क्षति हुई।
   - पर्यावरण एक वैश्विक सहाधिकार होने के नाते, एक या कुछ देशों के लिए इसका सतत उपयोग सुनिश्चित करना असंभव होने की अपेक्षा कठिन है। उसके लिए विश्वव्यापी सहयोग की आवश्यकता है।
   - विकासशील और कम से कम विकसित देशों की तुलना में ऐतिहासिक रूप से विकसित देशों ने ऊर्जा गहन विकास पथ का अनुसरण किया, जिससे वैश्विक सामुहिक धरोहर को अधिक नुकसान हुआ।
   - इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का होना और आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के सफल समाधानों का पता लगाना महत्त्वपूर्ण है।

2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिये:**
   - आज तक सतत् विकास पर तीन अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुए।
   - 1992 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में आयोजित पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) (लोकव्यापी रूप से रियो शिखर सम्मेलन या पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है)।
   - 2002 का सतत् विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ (लोकव्यापी रूप से रियो +10 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2002 के रूप में जाना जाता है)।
   - ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित 2012 के सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCSD) (लोकव्यापी रूप से रियो +20 या पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2012 के रूप में जाना जाता है)।

3. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिये:**
   - ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट का नाम ''हमारा सामूहिक भविष्य'' है।
   - पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना आर्थिक विकास की आवश्यकता को संबोधित करने में यह एक प्रकार की प्रथम रिपोर्ट थी।
   - रिपोर्ट ने ''सतत् विकास'' शब्द को परिभाषित और लोकप्रिय बनाया, अर्थात् विकास,जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना

होता है। इस परिभाषा ने अंतर–पीढ़ीगत समानता के महत्त्व पर अधिकार कर लिया है, जिसने पारंपरिक पर्यावरण नीति से सतत् विकास नीति को अलग किया।

- इस रिपोर्ट ने लोगों, संसाधनों, पर्यावरण और विकास के बीच अंतर्संबंधों को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में देशों के बीच सहयोग के माध्यम से वर्ष 2000 और उसके बाद के वर्षों तक सतत् विकास प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक पर्यावरणीय कार्यनीतियों का सुझाव दिया।

बोध प्रश्न 2

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहियेः**

- पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा। यह पर्यावरण और विकास पर 27 सिद्धांतों की एक राजनीतिक घोषणा थी। इसमें महिलाओं, स्वदेशी लोगों और पर्यावरण की दृष्टि से कमज़ोर देशों की विशेष ज़रूरतों पर प्रकाश डाला गया। इसने उत्पादन और उपभोग के अस्थायी प्रतिमानों को कम करने पर ज़ोर दिया।
- एजेंडा 21, सतत् विकास के विषय में संयुक्त राष्ट्र की गैर–अनिवार्य कार्रवाई योजना, जहां 21 को 21वीं शताब्दी के लिए संदर्भित किया गया है। विभिन्न लक्ष्यों और मुद्दों को चार वर्गों के अंतर्गत रखा गया था–सामाजिक और आर्थिक आयाम, विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन, प्रमुख समूहों की भूमिका को मज़बूत करना, और कार्यान्वयन के साधन।
- वन सिद्धांतों का विवरण। यह सभी प्रकार के वनों के प्रबंधन, संरक्षण और सतत् विकास पर वैश्विक सहमति के लिए सिद्धांतों का गैर–कानूनी रूप से अनिवार्य आधिकारिक कथन था।
- जलवायु परिवर्तन पर यू एन तंत्र सम्मेलन। जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने के लिए यह अंतरसरकारी संधि थी। UNFCCC का प्रमुख परिणाम क्योटो प्रोटोकॉल (1997) था।
- जैविक विविधता पर सम्मेलन। जैविक विविधता को कानूनी रूप से अनिवार्य संधि के रूप में योजनाबद्ध किया गया था। तीन मुख्य उद्देश्य–जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक विविधता के घटकों का स्थायी उपयोग, और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले लाभों का न्यायोचित उपयोग था। CBD–सी बी डी के प्रमुख आउटपुट थे– i) कार्टाजेना जैवसुरक्षा प्रोटोकॉल, ii) ऐची (Aichi) लक्ष्य, iii) नागोया आनुवंशिक संसाधन प्रोटोकॉल।

बोध प्रश्न 3

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहियेः**

- रियो +10 का आयोजन 2002 में जोहान्सबर्ग में किया गया था। इसने गरीबी उन्मूलन, बदलते उपभोग और उत्पादन प्रतिमान को बदलने और आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन आधार की रक्षा और प्रबंधन पर प्रकाश डाला।
- जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन का मुख्य केंद्र–बिंदु स्वच्छ पानी, पर्याप्त आश्रय, ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल, खाद्य–सुरक्षा और जैव–विविधता के संरक्षण के रूप में मौलिक आवश्यकताओं तक पहुंच।

- रियो +10 का प्रमुख परिणाम जोहान्सबर्ग घोषणा था, जो केवल विश्व नेताओं द्वारा सहमत होने के लिए एक राजनीतिक कथन के रूप में था, जो सतत् विकास की दिशा में काम करने की उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
- सतत् विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (रियो +20) 2012 में रियो डी जेनेरो, ब्राजील में आयोजित किया गया था। यह मूल रूप से एक 'समीक्षा' सम्मेलन की तरह था, जो 1992 के पश्चात् से हुई प्रगति का आकलन करेगा। इसलिए, इसके उद्देश्य पूर्व दो सम्मेलनों की अपेक्षा बहुत सीमित थे।
- दो विषयों को रियो +20 में प्राथमिक केंद्र–बिंदु सतत् विकास और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था और सतत् विकास के लिए संस्थागत ढांचे को प्राप्त हुआ। सम्मेलन का प्राथमिक परिणाम गैर–बाह्यकारी दस्तावेज 'जो भविष्य हम चाहते हैं' था।
- इस दस्तावेज़ का प्रमुख फोकस था, कैसे हरित अर्थव्यवस्था सतत् विकास को प्राप्त करने; यु एन ई पी को मज़बूत करने, जी डी पी से परे एक देश की भलाई का आकलन करने, जेन्डर समानता में सुधार करने, स्वदेशी ज्ञान को महत्त्व प्रदान करने, भूमि क्षरण की रोकथाम; स्थायी शहरों और शहरी बस्तियों की योजना बनाने, आपदाओं के जोखिम को कम करने के लिए विकासशील उपकरणों, महासागरों और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को सुधारने और उनकी जैवविविधता के बनाए रखने के उपकरणों के रूप में किया जा सकता है।
- रियो +20 में, सदस्य राज्यों ने एस डी जी को एक संग्रह को विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया आरंभ करने का निश्चय किया, जिससे कि एम डी जी के पद 2015 को बनाया जा सके।

2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहियेः**

- अधिकांश पर्यावरणीय समस्याएं प्रकृति में वैश्विक हैं और अधिकांश राष्ट्रीय सरकारें प्रायः वैश्विक समस्याओं की अपेक्षा राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने के लिए वित्तीय प्राथमिकता देती है।
- तीव्र वैश्वीकरण ने वैश्विक पर्यावरण के साथ–साथ अंतर और देश की आय असमानताओं पर नकारात्मक प्रभाव डाला, जो वैश्विक सतत् विकास की पूर्ण प्राप्ति के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई।
- अंतरराष्ट्रीय निर्णय–निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है, क्योंकि किसी भी कार्रवाई को करने से पूर्व कई राष्ट्रीय सरकारों का सहमत होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक निर्णय–निर्माण के स्तर पर बहुत कम लोकतांत्रिक जवाबदेही है। जिसके परिणामस्वरूप, कार्रवाई के लिए प्रभावी सार्वजनिक दबाव उत्पन्न करना कठिन है।
- कई अलग–अलग अंतरराष्ट्रीय संगठन, कार्यक्रम और निकाय हैं, जो वैश्विक स्तर पर सतत् विकास को संचालित करते हैं, जिसके परिणाम–स्वरूप प्रायः समग्र समाधान की अपेक्षा खंडित प्रक्रियाएँ होती हैं।
- ऐतिहासिक रूप से यह विकसित देशों ने विकासशील देशों की तुलना में वैश्विक जन को नुकसान पहुंचाने में अधिक योगदान दिया था। इस प्रकार, जब तक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यू एस ए जैसे विकसित देशों से अधिक प्रतिबद्धता सुनिश्चित नहीं करते, तब तक सफलता की संभावना बेरंग होगी।

इकाई 7 विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंधः विभेदित जिम्मेदारियों का केस*

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 विकास और सततता की अवधारणाएँ

7.3 जलवायु परिवर्तन : अर्थ और प्रभाव

7.4 सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत

7.5 विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंध

7.6 निष्कर्ष

7.7 शब्दावली

7.8 संदर्भ लेख

7.9 बोध प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप निम्नलिखित बाते समझ सकेंगे :

- विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन की अवधाराणाएं;
- सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत; और
- विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंध।

7.1 प्रस्तावना

विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया हैं, जो लोगों को उनकी मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने और गरीबी, असमानताओं और बेरोजगारी को कम करके उनके जीवन स्तर में सुधार करके उन्हें सक्षम बनाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति, बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अधिक प्रयोग ने सरकारों को उनके विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता की। ये उपलब्धियाँ औद्योगिक देशो में असमान और व्यापक रूप से सकेंद्रित है। यद्यपि विकसित राज्य आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में अपेक्षाकृत सफल सिद्ध हुए हैं, फिर भी पिछली अर्द्धसदी (Half-century) में बहुत अधिक प्रगति को पर्यावरण की सततता की कीमत पर प्राप्त किया गया है।

परिणामस्वरूप, वर्तमान विश्व कई आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय खतरों का सामना कर रहा है, जो सहभागिता को भयंकर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक–आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति की गतिशील ताकतों द्वारा किए गए दबावों ने पृथ्वी के परिस्थितिक संतुलन को मौलिक रूप से बदल दिया है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। हालाँकि, मानव ने संपूर्ण इतिहास में प्राकृतिक संसाधनों को अत्यधिक

* योगदानः डा. कनन अंबलम, सहायक प्रोफेसर और प्रमुख, लोक प्रशासन और विकास प्रबंधन विभाग, वोलेगा विश्वविद्यालय, नेकेमटे, इथियोपिया

उपयोग किया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिक समस्याएं अपेक्षाकृत अधिक मार्मिक रूप से प्रकट हो रही हैं।

आज वैश्विक जलवायु परिवर्तन का खतरा मानवता के लिए अभूतपूर्व चुनौतियाँ हैं। जलवायु परिवर्तन एक गंभीर विकास समस्या का प्रतिनिधित्त्व करता है, जिसे अब वास्तिविक, दबाव–देही और स्वाभाविक वैश्विक समस्या के रूप में स्वीकार किया गया है। जलवायु परिवर्तन की भविष्यवाणियों में कई अनिश्चितताएँ हैं, विशेष रूप से समय, परिमाण और क्षेत्रीय स्वरूप के संबंध में। ग्लोबल वार्मिंग के रूप में लोकप्रिय मानव–प्रेरित जलवायु परिवर्तन का खतरा, समाज के लिए एक कठिन चुनौती प्रस्तुत करता है। पिछले कुछ दशको में, मानव गतिविधि के परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैसों (Greehouse Gases-GHG-जी एच जी) के उत्सर्जन की दर में तेजी से वृद्धि हुई है, मुख्य रूप से कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म ईंधन जलने के कारण सामान्यीकृत रूप से पृथ्वी की सतह को गर्म करने का संचालन करते हैं।

आज कोई भी देश जलवायु परिवर्तन से मुक्त नहीं है। लेकिन विकासशील अर्थव्यवस्थाएं आशिंक रूप से जलवायु के भय के अधिक प्रभाव के कारण और आंशिक रूप से उनकी कम अनुकूली क्षमता के कारण अधिक प्रभावित होती है। जबकि औद्योगिक देशों की ऊर्जा और संसाधन–गहन उत्पादन व खपत के तरीके जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से हैं, विश्व के दक्षिण भागो के देशों में गरीब लोग हैं, जो इसके प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। इन देशों में सबसे कम सामना करने की क्षमताएं है और इन्होंने जलवायु परिवर्तन में कम से कम योगदान दिया है।

मध्य–शताब्दी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था के चौगुने होने के साथ, ऊर्जा से संबंधित कार्बन डाईऑक्साइड (Carbon Dioxide-CO_2) का उत्सर्जन, वर्तमान प्रवृत्तियों पर, दोगुने से अधिक, दुनिया को संभावित विनाशकारी प्रक्षेपवक्र (Catastrophic Trajectory) पर डाल देगा, जिस कारण पूर्व–औद्योगिक समय की तुलना में तापमान 50 से अधिक गर्म हो सकता है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की जटिल प्रकृति सभी देशों द्वारा व्यापन संभव सहयोग के लिए और उनकी प्रभावी भागीदारी और उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, उनकी सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के अनुसार आवश्यक होती है।

सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियाँ, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि सभी राज्य वैश्विक पर्यावरण विनाश के लिए जिम्मेदार हैं, फिर भी समान रूप से जिम्मेदार नहीं हैं। यह सिद्धांत जलवायु परिवर्तन सहित पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करने के लिए सभी वैश्विक प्रयासों के मूल रूप में बना है।

7.2 विकास और सततता की अवधारणाएँ

विकास की अवधारणा

विकास के कई तत्त्व हैं और उन्हें परिभाषित करना कठिन है। इसे लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में, आर्थिक और मानव विकास के संदर्भ में और सततता के संदर्भ में देखा जा सकता है। विकास का अर्थ मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना, गरीबी, असमानता और बेरोजगारी को कम करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि करना, व आर्थिक और सामाजिक विकल्पों का विस्तार करना है। विकास का तात्पर्य है आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के साथ जटिल समाज का समस्त परिवर्तन। विकास का संबंध निरंतर और अपरिवर्तनीय आर्थिक विकास से है, जिसका वर्णन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि और किसी दिए गए देश के कुछ संरचनात्मक और सामाजिक परिवर्तन के साथ मात्रात्मक मामलों में होगा।

विकास व आर्थिक विकास पर्याय नहीं हैं। विकास राष्ट्रीय आय में वृद्धि और एकल–दिशा स्वरूप से संबंधित है। विकास मनुष्यों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के विषय में है, और यह आवश्यक नहीं कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद या जी एन पी (Gross National Product-GNP) में वृद्धि हो। विकास की कल्पना एक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में की जानी चाहिए, जिसमें संपूर्ण आर्थिक और सामाजिक प्रणालियों का पुनर्गठन शामिल है। राष्ट्रीय आय में सुधार के अतिरिक्त, इसमें आम तौर पर संस्थागत, सामाजिक और प्रशासनिक संरचनाओं के साथ–साथ लोकप्रिय दृष्टिकोणों और यहां तक कि रीति–रिवाजों और मान्यताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्मिलित है। महत्वपूर्ण रूप से, आर्थिक विकास, विकास के महत्वपूर्ण साधनों में से एक है।

विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में मौलिक जीवन निर्वाह योग्य वस्तुएं – भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि की उपलब्धता और वितरण में वृद्धि करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए उच्च स्तर की आय, अधिक रोजगार, बेहतर शिक्षा, आदि में वृद्धि करना और व्यक्तियों और राष्ट्रों के लिए उपलब्ध आर्थिक और सामाजिक विकल्पों की सीमा का विस्तार करना शामिल है।

जीविका, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता विकास के कुछ प्रमुख मूल्य हैं, जिन्हें विकास के आंतरिक अर्थ को समझने के लिए वैचारिक आधार और व्यावहारिक दिशानिर्देश के रूप में उपयुक्त होना चाहिए। ये सभी व्यक्तियों और समाजों द्वारा प्रयास किए गए सामान्य लक्ष्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं से संबंधित है, जो हर समय लगभग सभी समाजों और संस्कृतियों में अपनी अभिव्यक्ति प्राप्त करते हैं।

ये मुख्य मूल्य उन संकेतकों में प्रतिबिंबित होते हैं, जो विकास को मापने में उपयोग किए जाते हैं। पूर्व–1970 के दशक में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की क्षमता के संदर्भ में विकास को उसकी राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दिखाने के लिए या राष्ट्र की अपनी जनसंख्या की वृद्धि दर की तुलना में तेजी से एक दर पर अपने उत्पादन का विस्तार करने की क्षमता के रूप से मापा गया था। यह केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के भौतिक विस्तार से संबंधित है।

विकास के इन सरलीकृत, संकीर्ण रूप से परिभाषित संकेतकों की आलोचना की गई, क्योंकि उन्होंने संपूर्ण जनसंख्या के बीच आय के वितरण को प्रतिबिंबित नहीं किया था। इसके अतिरिक्त, यह कुछ कारको को ध्यान में रखने में विफल रहा, जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इन चिंताओं को संबोधित करने के लिए, विकास को मापने के लिए नए संकेतकों का उपयोग किया गया। ये संकेतक थे – मानव विकास सूचनांक (Human Development Index -HDI-एच डी आई), मानव गरीबी सूचनांक (Human Poverty Index -HPI-एच पी आई), जेन्डर–संबंधित विकास सूचकांक (Gender-related Development Index -GDI-जी डी आई) और जेंडर सशक्तिकरण उपाय (Gender Empowerment Measure -GEM-जी ई एम) हैं।

HDI (एच डी आई) मानव विकास के तीन मूलभूत आयामों में एक देश की औसत उपलब्धियों को मापता है। दीर्घ और स्वस्थ जीवन (जीवन प्रत्याशा-Life Expectancy), ज्ञान (प्रौढ साक्षरता- Adult Literacy) और एक सभ्य जीवन स्तर (खरीदने की क्षमता की समता-Purchasing Power Parity -PPP-पी पी पी)। जबकि मानव विकास की अवधारणा किसी भी समग्र सूचनांक की तुलना में अधिक व्यापक हो सकती है, जिसे मापा जा सकता है। ये समग्र मानव विकास सूचनांक मानव कल्याण के संक्षिप्त उपाय के रूप में आय के लिए शक्तिशाली विकल्प प्रदान करते हैं।

HPI (एच पी आई) समुदाय में गरीबी के विस्तार पर सामूहिक निर्णय पर पहुँचने के लिए जीवन की गुणवत्ता में अभाव की विभिन्न विशेषताओं को समग्र सूचनांक में एक साथ लाने का प्रयास है। मानव गरीबी (Human Poverty) मुख्य रूप से केवल आय

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

की अपेक्षा जीवन जीने के लिए विकल्पों और अवसरों से संचित है। इसलिए आय का अभाव समग्र गरीबी सूचक के रूप में काम करने के लिए बहुत संकीर्ण है।

GDI (जी डी आई) उन्हीं मौलिक क्षमताओं में उपलब्धि को मापता है, जैसा कि एच डी आई करता है, लेकिन महिलाओं और पुरूषों के बीच उपलब्धि में असमानता को ध्यान में रखता है। जी डी आई राजनीतिक और आर्थिक मंचों पर महिलाओं के आगे बढ़ने में प्रगति का मूल्यांकन करता है। यह जाँच करता है कि आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महिलाएं और पुरूष किस सीमा तक सक्रिय रूप से भाग ले सकते हैं और निर्णय निर्माण में भाग लेते हैं।

पिछली दो शताब्दियों में कार्बन–गहन विकास (Carbon-intensive) के प्रत्यक्ष लाभ को बड़े पैमाने पर विकसित देशों में केंद्रित किया गया है। दूसरी ओर, विकासशील देशों के विकास के अनुभव महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय और गरीबी का निम्न स्तर कृषि सहित उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादकता के निम्न स्तर के कारण है। इसके अतिरिक्त, पूँजी निर्माण के निम्न स्तर – दोनों भौतिक और मानव, तकनीकी प्रगति की कमी और तेजी से जनसंख्या वृद्धि विकासशील देशों की कुछ अन्य सामान्य विशेषताऐं हैं।

आईए इसे उदाहरणों से समझते हैं, विकासशील देशों में लगभग जनसंख्या का आधा भाग (48 प्रतिशत) अभी भी गरीबी में है, वे प्रतिदिन 2 डौलर से कम पर जीवन व्यतीत करते हैं। लगभग एक चौथाई यानि 1.6 बिलियन लोगों के पास बिजली नहीं है और छह में से एक की स्वच्छ पानी तक पहुँच में कमी है। लगभग 10 मिलियन के करीब बच्चे अभी भी श्वसन संक्रमण, खसरा और दस्त (Respiratory Infections, Measles, and Diarrhoea) जैसे निवारण और उपचार योग्य रोगों से प्रत्येक वर्ष मर जाते हैं। विकासशील देशों में अधिक जनसंख्या ने पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव डाला, भूमि और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया और ऊर्जा की माँग में वृद्धि की। यह पर्यावरण की सततता को प्रभावित करता है और विकास प्रक्रिया से समझौता करता है।

सततता की अवधारणा

सततता एक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाओं या सामाजिक प्रथाओं के समूह की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को प्रस्तुत करती है। यह विचार आधुनिक पर्यावरण आंदोलन के साथ प्रमुखता से उभरा, जिसने समकालीन समाजों के असतत स्वरूप की निन्दा की, जहाँ प्रकृति के संसाधनों का उपयोग, विकास की दिशा ओर खपत के प्रतिरूप पारिस्थितिक तंत्र की अखंडता और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिए खतरा है।

सततता की अवधारणा किसी वस्तु की स्थिति या गुणवत्ता है, जो किसी अन्य वस्तु को बनाए रख सकती है, उसकी रक्षा कर सकती है, व उसे पोषित और संरक्षित कर सकती है। इस इकाई के संदर्भ में, सततता मानव पर्यावरणीय प्रणाली की गुणवत्ता को प्रस्तुत करता है। एक प्रणाली के स्तर या गुणवत्ता को निर्धारित करने या मापने के लिए सततता को एक मात्रात्मक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। यह माप संकेतक और सूचकांक की आवश्यकता होती है। यह माप संकेतक और सूचकांक के माध्यम से और अन्य साधनों के बीच किया जा सकता है।

समकालीन विचार–विमर्श में, सततता प्रायः सतत विकास के पर्याय के रूप में कार्य करती है। सततता का संबंध ऐसी प्रणाली की गुणवत्ता से है, जो पर्यावरण और मानवीय पहलुओं के निरंतर एकीकरण से संबंधित है। यदि उत्पादन (विकास) सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है, तो पर्यावरण प्रणाली (सततता) की योग्यता प्रभावित होगी। इसलिए, सतत विकास सततता प्राप्त करने की कुंजी है, जिसे अंतिम दीर्घकालिक लक्ष्य माना जाता है। दूसरे शब्दों में, सतत विकास का अर्थ

है कि एक गतिविधि या प्रक्रिया को बनाए रखना सुनिश्चित करता है कि एक प्रणाली दीर्घकालिक रूप में काम करती है।

इस प्रकार, सततता में प्रणाली और सतत विकास को सम्मिलित किया जाता है, जो मानवीय आवश्यकताओं और उनकी वर्तमान और भविष्य की भलाई की ओर देखती है। मानव और पर्यावरण प्रणाली के समुचित एकीकरण के माध्यम से सततता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रणाली के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के संरक्षण को सतत विकास प्रक्रिया में अवश्य ही एकीकृत करना चाहिए।

पारिस्थितिक पदचिह्न सततता का माप है। यह एक व्यक्ति, शहर या राष्ट्र द्वारा उपभोग किए गए संसाधनों को प्रदान करने के लिए आवश्यक भौतिक क्षेत्र का माप है। यह मान्यता के आधार पर सततता का माप है, जब संसाधनों का उपयोग उसके उत्पादन की अपेक्षा अधिक किया जाता है, तो संसाधन तेजी से समाप्त हो जाते हैं।

समानांतर संदर्भ भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे :

पर्यावरणीय सततता (Environmental Sustainability): किसी गतिविधि या गतिविधियों के समूह का समर्थन करने के लिए पर्यावरण संसाधनों की योग्यता।

आर्थिक सततता (Economic Sustainability): आर्थिक लागत से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए किसी गतिविधि या गतिविधियों के समूह की योग्यता।

सामाजिक सततता (Social Sustainability): किसी गतिविधि को क्षति पहुँचाएं बिना उसका समर्थन करने के लिए सामाजिक संरचनाओं और या/व्यवहार की योग्यता।

7.3 जलवायु परिवर्तन : अर्थ और प्रभाव

पृथ्वी के जलवायु में परिवर्तन और इसके प्रतिकूल प्रभाव मानव जाति की एक सामान्य चिंता है। जलवायु परिवर्तन एक बड़ी वैश्विक चुनौती है। जलवायु परिवर्तन 1970 से 80 के दशक के पश्चात् से वैश्विक वार्षिक औसत तापमान में तेजी के रूझान से वैश्विक मुद्दे के रूप में सामने आया। मानव गतिविधियों ने जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन यह परिवर्तन पहले की तुलना में कहीं अधिक तीव्र और खतरनाक हैं। जलवायु परिवर्तन को स्थानीय, क्षेत्रीय या बड़े पैमाने पर परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो दीर्घकालिक औसत शासन की जलवायु से संबंधित तापमान, तेजी, प्रसार और प्रभावित करने वाले कारकों की विशेषताओं को दर्शाता है। तापमान में वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप होने वाले पर्यावरणीय परिणामों के कारण इसे वैश्विक महत्व का मुद्दा माना जाता है अर्थात इसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दा माना जाता है। यह सीमा पार भी उत्पन्न होती है – जलवायु परिवर्तन राष्ट्र–राज्य द्वारा सीमांकित सीमाओं का ध्यान नहीं करतें।

जीवाश्म ईधन (Fossil Fuel) की खपत में बड़े पैमाने पर कारखानों और बिजली संयंत्रों, मोटर वाहनों और घरों द्वारा अधिक से अधिक कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस जलाने की वृद्धि के साथ आर्थिक विकास भी हुआ है। इससे विशाल कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon Dioxide-CO_2) गैस का उत्सर्जन होता है। यह ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा स्रोत है, जो पृथ्वी से अपने वायुमंडल में अवरक्त (Infrared) विकिरण को फंसा कर ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) पैदा कर सकता है।

ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के मामले में, उनके बीच महत्वपूर्ण अंतर के साथ कुछ छह अलग–अलग ग्रीन हाउस गैसें हैं। वे अवरक्त विकरण (Infrared Radiation) की कुछ लंबी तरंगों को अवशोषित करते हैं, जो पृथ्वी को छोड़ रही होती है और इस प्रकार वे वातावरण का तापमान बढ़ाते हैं, इसलिए इन गैसों को 'ग्रीन हाउस' गैसों के रूप में जाना जाता है। ग्रीनहाउस गैसों (GHG) के विविध स्रोत हैं।

जलवायु परिवर्तन विकास पर अद्वितीय पैमाने का बोझ डालते हैं। इसके प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहे हैं, और सबसे आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते हैं कि ग्रीनहाउस गैस (GHG-जी एच जी) उत्सर्जन की वर्तमान दर को देखते हुए समस्या तेजी से बिगड़ रही है। जलवायु परिवर्तन, कृषि वानिकी, ऊर्जा और तटीय क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों और उत्पादक वातावरण को प्रकाशित करता है।

गरीबी और सकल घरेलू उत्पाद या जी डी पी (Gross Domestic Product) के लिए इस तरह के जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ विकासशील देशों में प्रक्षेपित जनसंख्या वृद्धि को बहुत बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, उप–सहारा अफ्रीका के प्रमाण संकेत देते हैं कि वर्षा में परिवर्तनशीलता, जो कि वास्तव में वृद्धि के लिए प्रक्षेपित है, जी डी पी को भी कम करती है और गरीबी को भी बढ़ाती है।

जलवायु परितर्वन के मुख्य प्रभावों में शामिल हैः

- स्थानीय औसत तापमान और चरम सीमा में वृद्धि–भूमि और पानी दानों;
- वर्षा प्रतिरूप में परिवर्तन– इसका आरंभ, मौसमी वितरण और चरम सीमा;
- बड़े तूफानों और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों (Tropical Cyclones) की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि;
- पौधों और पानी की सतहों से वाष्पीकरण (Evaporation) के नुकसान में वृद्धि;
- ग्लेशियरों (Glaciers) और अन्य बर्फ निकायों के पिघलने में वृद्धि, जो समुद्र के स्तर में वृद्धि और समुद्र के अम्लीकरण (Acidification) में वृद्धि करते हैं;
- निरंतर गंभीर सूखा और बाढ़;
- तूफानों में उच्च हवा से अधिक नुकसान;
- अलग–अलग कीटों, बीमारियों और पानी की आवश्यताओं के साथ बाधित फसल कैलेंडर;
- गर्मी के लहरें और नए क्षेत्रों में बीमारी का प्रसार (जैसे मलेरिया); तथा
- पानी की मांग में वृद्धि और पानी उपलब्धता में कमी।

1970 और 1980 के दशक में वैश्विक वायुमंडलीय प्रदूषकों और उनके वैश्विक परिणामों अर्थात् जलवायु परितर्वन पर अधिक ध्यान दिया गया। मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (United Nations Conference on the Human Environment, 1972) ने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उठाया। इसी तरह, 1974 और 1976 में, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य सम्मेलन (United Nations World Food Conferences) ने जलवायु परिवर्तन पर एक दबाव के रूप में चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और विश्व मौसम संगठन (United Nations Environment Programme and the World Meteorological Organisation) ने 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतःसरकारी पैनल (Intergovernmental Panel on Climate Change -IPCC) के गठन का नेतृत्व किया। यह संगठन मौजूदा जलवायु मॉडल और साहित्य के अनुसार ग्रीनहाउस के प्रभाव की भविष्यवाणी करने का प्रयास करता है।

1992 में, रियो अर्थ शिखर सम्मेलन (Rio Earth Summit) में, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन (United Nations Framework Convention on Climate Change- UNFCC) पर 154 राज्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। UNFCC ने जी एच जी को एक स्तर पर स्थिर करने का लक्ष्य रखा, जो जलवायु प्रणाली के आगे के हस्तक्षेप को रोक देगा। इस सम्मेलन के पक्षकारों ने 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल (Kyoto Protocol) को भी अपनाया, जो देश इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे इन गैसों के उत्सर्जन को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए GHG को कम करने या उत्सर्जन व्यापार में

संलग्न होने के लिए प्रतिबद्ध है। क्योटो प्रोटोकॉल के अधिकांश प्रावधान विकसित देशों पर लागू होते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत को अपनाता है।

यह सिद्धांत उन विकसित देशों की जरूरतों पर जोर देता है, जिन्होंने वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं और उनके उच्च आर्थिक धन और उन्नत तकनीकी क्षमताओं को अपना ऐतिहासिक और वर्तमान योगदान दिया है, जो प्राकृतिक संसाधनों के बड़े पैमाने पर शोषण को सक्षम करते हैं, इन्हें पर्यावरण की सुरक्षा के उपायों को लागू करने में प्रमुख जिम्मेदारी लेनी चाहिए। प्रोटोकॉल के तहत, औद्योगिक देशों को अपने जी एच जी के उत्सर्जन को कम करना आवश्यक है। यह उस सिद्धांत की भी पुष्टि करता है कि विकसित देशों को जलवायु से संबंधित अध्ययनों और परियोजनाओं के लिए अन्य देशों को प्रौद्योगिकी की आपूर्ति का भुगतान करना है।

बोध प्रश्न 1

नोट : i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. विकास और सततता की अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए।

....

....

....

....

2. जलवायु परितर्वन के अर्थ और प्रभाव को स्पष्ट कीजिए।

....

....

....

....

7.4 सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत

विश्व इतिहास के किसी भी संकट ने जलवायु परिवर्तन सहित समकालीन वैश्विक पर्यावरणीय संकट के रूप में सरकारों की बढ़ती परस्पर निर्भरता और राज्यों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया है। वे राष्ट्रीय सीमाओं को पार करके, कार्यक्षेत्र में वैश्विक हो रहे हैं, और विश्व की जनसंख्या और प्राकृतिक संसाधनों के सभी या संपन्न भागों को प्रभावित कर रहे हैं। पर्यावरणीय समस्याओं की जटिल प्रकृति का वर्णन वैज्ञानिक अनिश्चिताओं की महत्वपूर्ण स्थिति से संबंधित उनके कारणों, प्रभावों, प्रतिक्रिया और जटिल प्राकृतिक या सामाजिक मापदंडों के बीच अंतरसंबंधों द्वारा किया जाता है।

आज पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने के लिए सभी वैश्विक प्रयास सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत द्वारा संचालित होते हैं। यह इस बात का समर्थन करता है कि वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं का सामना करने के लिए सभी राज्यों को जिम्मेदारियाँ उठाने की आवश्यकता है। यह स्वीकार करता है कि विकास के उच्च स्तरों और वैश्विक पर्यावरणीय संसाधनों जैसे हवा और पानी के घटाव में अधिक योगदान के बीच ऐतिहासिक सहसंबंध है और इसके अनुसार ही ज़िम्मेदारियों को बांटने में सक्षम बनाता है। यह उन विकसित देशों को स्थापित करता है, जो पर्यावरण प्रतिबंधों द्वारा

बिना रूकावट के लंबे समय तक विकास करने में सक्षम है। अब उन्हें जिम्मेदारियों का अधिकांश भाग लेने की आवश्यकता है।

सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत (Principle of Common, but Differentiated Responsibilities) के उद्भव को स्टाकहोल्म सम्मेलन (Stockholm Conference, 1972) से समझा जा सकता है। यह संयुक्त राष्ट्र या संयुक्त राष्ट्र सममेलन का पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रथम वास्तविक या ठोस (Tangible) प्रयास है, जिसने पर्यावरण और गरीबी की समस्याओं पर प्राथमिक लेख प्रस्तुत किया, जिसे फॉनेक्स रिपोर्ट (Founex Report) कहा जाता है। फॉनेक्स रिपोर्ट ने पर्यावरण और विकास के प्रति अपने दृष्टिकोण में विकासशील और औद्योगिक देशों के बीच अंतर को कम करने का प्रयास किया। इस अग्रणी दस्तावेज ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति राष्ट्रों में विभेदित जिम्मेदारियों को समर्थन किया। इसने पर्यावरण की मांगों और गरीब राष्ट्रों के आर्थिक विकास की आवश्यकता को संतुलित करने पर जोर दिया। इसे 1992 में रियो डी जेनेरो (Rio de Janeiro) में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (United Nations Environment and Development Conference- UNEDC) के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर औपचारिक रूप दिया गया।

कानूनी शब्दावली में, सामुहिक लेकिन विभेदत जिम्मेदारियों का सिद्धांत एक विशेष पर्यावरणीय संसाधन के संरक्षण के दिशा में दो या दो से अधिक राज्यों के सांझे दायित्व का वर्णन करता है। दूसरी ओर, विभिन्न विभेदित स्तरों को स्थापित करने की आवश्यता है, जिस पर विभिन्न राज्य अपनी क्षमता और समस्या के लिए अपने स्तर के योगदान के अनुसार प्रभावी रूप से एक सामूहिक प्रतिक्रिया (Collective Response) में प्रवेश कर सकते हैं। इसके अनुसार, विकसित देशों के लिए यह अनिवार्य है कि वह विकासशील देशों को अपने वैश्विक सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने के लिए, प्रौद्योगिकी और वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण के रूप में सहायता प्रदान करे। यह सिद्धांत जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में लागू करने के लिए अधिक उपयुक्त है।

जबकि, जलवायु परितर्वन के परिणामस्वरूप दुनिया भर में गतिविधियाँ होती हैं, इससे देशों में बहुत अधिक विभिन्न प्रभाव पड़ सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का सबसे बुरा प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ेगा। आंशिक रूप से उनके भौगोलिक स्थान के कारण व आंशिक रूप से उनकी कमजोर सामना करने के क्षमताओं के कारण, जो उनकी कमजोर सामाजिक, संस्थागत और भौतिक अवसंरचनाओं के कारण होती हैं। विकसित देश अब वायुमंडल में संचित ऊर्जा से संबंधित जी एच पी के लगभग दो–तिहाई के लिए जिम्मेदार है। वे विकासशील देशों की तुलना में औसतन प्रति व्यक्ति ऊर्जा का 5 गुना अधिक उपभोग करते हैं। जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए विकसित देशों को नेतृत्व करना होगा। उदाहरण के लिए, ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) में संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा योगदान है। हालाँकि, इसमें दुनिया की जनसंख्या का केवल 4 प्रतिशत भाग है। लेकिन यह वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 25 प्रतिशत उत्पादन करता है।

वैश्विक जी एच जी (GHG) उत्सर्जन को सीमित करने के लिए एक न्यायसंगत दृष्टिकोण को पहचानना होगा, जैसे कि विकासशील देशों की कानूनी विकास की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं होती हैं, उनका विकास जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है, और यह कि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से समस्या में बहुत कम योगदान दिया है। ऐतिहासिक और वर्तमान वैश्विक जी एच जी उत्सर्जन का सबसे बड़ा भाग विकसित देशों में उत्पन्न हुआ है, विकासशील देशों में प्रति–व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी अपेक्षाकृत कम है।

सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुसार, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए व्यापक कार्रवाई वैश्विक सहयोग के बिना संभव नहीं है। विकसित से विकासशील देशों की ओर जलवायु वित्त का प्रवाह जलवायु समस्या को संबोधित करने में प्रभावशीलता और दक्षता के साथ न्याय–संगतता समाधान के लिए प्रमुख साधनों का प्रतिनिधित्व करता है। वित्तीय प्रवाह विकासशील देशों को अपने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को अनुकूल बनाने में सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, नई तकनीकों को विकसित और प्रसारित करने से संबंधित वित्तीय आवश्यकता होगीं।

7.5 विकास, सततता और जलवायु परितर्वन के बीच परस्पर संबंध

विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन की अवधारणाओं के बीच विविध संबंध विद्यमान हैं। कई देशों में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सतत विकास को रोक रहा है या यहाँ तक कि मौजूदा विकास लाभ को नष्ट कर रहा है। आज, वास्तविक चुनौती अन्य सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ–साथ पर्यावरणीय प्रदर्शन में नाटकीय रूप से सुधार करना है। यदि हमें जलवायु परिवर्तन को सार्थक रूप से दूर करना है, तो विकास संबंधित मामलों और जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। प्रतिस्पर्धी मांगों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन की दोषपूर्णता को कम करने के लिए, समाजों का इन संसाधनों की रक्षा के साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों से अधिक उत्पादन को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। पर्यावरणीय सततता महत्वपूर्ण है।

औद्योगिक क्रांति के पश्चात् से ग्रीनहाउस गैसों की अत्यधिक वृद्धि ने लोगों और पर्यावरण के बीच संबंधों को परिवर्तित कर दिया है। दूसरे शब्दों में, जलवायु न केवल विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, बल्कि विकास की दिशा भी पृथ्वी की जलवायु को समान रूप से प्रभावित करती हैं। अप्रबंधित को छोड़कर, जलवायु परिवर्तन राष्ट्रों द्वारा प्राप्त विकास प्रगति को पीछे कर देगा और वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की भलाई के साथ समझौता करना पड़ेगा। यह निश्चित है कि पृथ्वी अभूतपूर्व गति से औसतन गर्म हो जाएगी।

विश्व के सबसे गरीब देश भी ऐसे हैं, जो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते है। कई देशों और क्षेत्रों के लिए, न केवल आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक उपलब्धियाँ दाँव पर है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। बरसात के और पतझड़ के मौसम बदल रहे हैं। वर्षा लगातार परिवर्तनशील और अप्रत्याशित होती जा रही है। फसलें मुरझा जा रही हैं या बाढ़ में बह रही हैं। मलेरिया जैसे रोग नए क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं। उष्णकटिबंधीय (Tropical) बीमारियाँ उत्तर में फैल सकती है, और बाढ़ से शीलवंत और नम क्षेत्रें में एक बड़ी समस्या बन जाएगी। आगे चलकर अर्थात् भविष्य में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में, कई विकासशील देशों में सुरक्षित पानी की स्थिति और भी खराब हो सकती है। बड़ी संख्या में लोगों को समुद्र के स्तर में वृद्धि होने से स्थानान्तरित किया जा सकता है, जिसमें अकेले बाग्लादेश में 100 लाख लोग शामिल है, साथ ही संपूर्ण राष्ट्र नीचे स्तर वाले द्वीपों जैसे कैरिबियन (Caribbean) में बसे हुए हैं।

एक देश के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की मात्रा मुख्य रूप से उसकी अर्थव्यवस्था के आकार, इसके औद्योगीकरण के स्तर और प्रकृति और उसकी ऊर्जा खपत की क्षमता पर निर्भर करता है। भले ही विकासशील देशों में विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग रहता हो, लेकिन औद्योगिक उत्पादन और ऊर्जा की खपत प्रतिव्यक्ति अपेक्षाकृत कम है।

सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुसार, विकसित देश अब तक, जी एच जी के सबसे बड़े उत्सर्जक देश रहे हैं, और अब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिए मुख्य जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। वैश्विक पर्यावरण पर विकसित समाजों ने जो बोझ डाला हुआ है, उससे महत्त्वपूर्ण कटौती करने की आवश्यकता है, जिसके लिए स्थापित स्वरूप के उत्पादन और खपत और ऊर्जा, परिवहन, निर्माण, विनिर्माण और कृषि सहित प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में आकस्मिक परिवर्तन की आवश्यकता है। अल्पीकरण, अनुकूलन और प्रौद्योगिकियों का परियोजन इस तरह से होना चाहिए कि जो विकासशील देशों को अपने विकास को जारी रखने और गरीबी को कम करने के लिए अनुमति दे। यही कारण है कि विकासशील देशों के लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रवाह अधिक महत्वपूर्ण है।

विकसित देशों को भी विकासशील देशों में कम कार्बन वृद्धि के लिए परितर्वन को बढ़ावा देने और पूँजी लगाने अर्थात् वित्त की आवश्यकता है। चुनौती को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों के लिए प्राकृतिक संसाधन प्रवबंधन, ऊर्जा प्रावधान, शहरीकरण, सामाजिक सुरक्षा जाल, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थानान्तरण, तकनीकी अनुसंधान और शासन में मौलिक परिवर्तन और ज्ञात व्यवसायों के बेहतर उपयोग की आवश्यकता है।

बोध प्रश्न 2

नोट : i) अपने उत्तरों के लिए नीचे दिये गये स्थान का प्रयोग कीजिए।

ii) इकाई के अंत में दिये गये उत्तरों से अपने उत्तर मिलाइए।

1. सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए।

....

....

....

....

2. विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच परस्पर संबंधों का परीक्षण कीजिए।

....

....

....

....

7.6 निष्कर्ष

विकास एक बहुआयामी (Multidimensional) प्रक्रिया है, जो लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने और गरीबी, असमानता और बेरोजगारी को कम करके उनके जीवन स्तर में सुधार करने के योग्य बनाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति, बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण और प्राकृतिक संसाधनों के अति–दोहन (उपयोग) ने सरकारों को उनके विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता की। यद्यपि मानव ने संपूर्ण इतिहास में प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है, लेकिन आज की पारिस्थितिक समस्याएँ जैसे जलवायु परिवर्तन अपेक्षाकृत आधुनिक घटनाएँ है। जबकि औद्योगिक देशों के उत्पादन के लिए ऊर्जा और संसाधन की अत्यधिक तरीके

और सेवन प्रतिरूप जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारणों में से है। दक्षिण विश्व के देशों में गरीब लोग रहते है, जो इसके प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। वैश्विक जलवायु परिवर्तन की जटिल प्रकृति सभी देशों द्वारा व्यापक संभव सहयोग और उनकी सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के अनुसार एक प्रभावी और उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में उनकी भागीदारी की मांग करती है।

सतत विकास सततता प्राप्त करने की कुंजी है, जिसे अंतिम दीर्घकालिक लक्ष्य माना जाता है। दूसरे शब्दों में, सतत विकास का अर्थ है कि एक गतिविधि या प्रक्रिया को सतत रखना सुनिश्चित करता है कि प्रणाली लंबे समय तक काम करती है। जलवायु परिवर्तन विकास पर एक अद्वितीय पैमाने को बोझ डालता है। इसके प्रभाव पहले से ही दिखाई दे रहे है, और सबसे आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाण दर्शाते है कि ग्रीनहाउस गैस (जी एच जी) उत्सर्जन की वर्तमान दर को देखते हुए समस्या तेजी से बिगड़ रही है। पश्चिमी यूरोप में जुलाई 2021 की बाढ़ अपने मे एक बड़ा मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन, कृषि, वानिकी, ऊर्जा और तटीय क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों और उत्पादक वातावरण को प्रभावित करता है।

सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों का सिद्धांत एक विशेष पर्यावरणीय संसाधन की सुरक्षा के लिए दो या दो से अधिक राज्यों के सांझें कर्त्तव्यों का वर्णन करता है। दूसरी ओर, विभिन्न स्तरों को स्थापित करने की आवश्यकता है, जिस पर विभिन्न राज्य अपनी क्षमताओं के अनुसार और समस्याओं के समाधान करने के लिए अपने योगदान के स्तर दोनों के अनुसार प्रभावी रूप से सामूहिक प्रतिक्रिया में प्रवेश कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए व्यापक कार्रवाई वैश्विक सहयोग के बिना संभव नहीं है, जिसके लिए सभी देशों द्वारा सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुसार समान व्यवहार की आवश्यकता होती है।

विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच विविध संबंध विद्यमान है। कई देशों में ग्लोबल वार्मिग का प्रभाव सतत विकास को रोक रहा है, या यहाँ तक कि मौजूदा विकास लाभ को भी नष्ट कर रहा है। आज, वास्तविक चुनौती अन्य सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करते हुए पर्यावरण के प्रदर्शन के आक्समिक रूप से सुधार करना है। प्रतिस्पर्धा मांगों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति दोषपूर्णता को कम करने के लिए, समाजों को इन संसाधनों की रक्षा के साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों से अधिक उत्पादन को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। इसलिए पर्यावरण की सततता महत्वपूर्ण है। इस इकाई ने सतत विकास और जलवायु परिवर्तन के बीच इन प्रासंगिक संबंधों का परीक्षण किया है।

7.7 शब्दावली

कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprints): एक उद्यमी, जो पर्यावरण के लिए सही काम करना चाहता है, उसके लिए कंपनी के कार्बन पदचिह्न की गणना करना उपयोगी है। इसका अर्थ है कि सभी व्यावसायिक गतिविधियों में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) समतुल्य उत्सर्जन को व्यक्त करना, जो अपने पर्यावरणीय प्रभाव को मापने और सतत व्यवसाय प्रर्कियाओं को अपनाकर प्रगति की ओर अग्रसर होने का रास्ता दिखाते हैं।

जलवायु परिवर्तन (Climate Change): जलवायु का परिवर्तन, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव गतिविधि के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो वैश्विक वातावरण की संरचना को बदल देता है और जो तुलनीय समय अवधि में देखी गई प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता के अतिरिक्त है।

विभेदित जिम्मेदारियां (Differentiated Responsibilities): सामुहिक लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों द्वारा पारिस्थितिक संतुलन बनाने के लिए विश्व राज्यों को प्रोतसाहित

किया जा रहा है। इसका अर्थ है कि सभी राज्य या देश पर्यावणीय निम्नीकरण के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन समान रूप से नही। इस अवधारणा को औपचारिक रूप 1992 में रियो डी जेनेरो (Rio de Janeiro) मे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन (UN Conference on Environment and Development- UNCED) के वैश्विक नियमो मे मिला। इसने आर्थिक विकास के स्तर के आघार पर पर्यावरण संरक्षण के प्रति राष्ट्रों में विभेदित जिम्मेदारियों का समर्थन किया।

ग्रीनहाउस प्रभाव (Greenhouse Effect): वह प्रर्किया जिसमें पृथ्वी ग्रह के वातावरण का विकरण पूरी सतह को गरमा देता है। यह विकरण ग्रीनहाउस गैसों से उत्पन्न होता है, जो प्राकृतिक संसाधनो के र्दुउपयेाग के कारण होता है।

ग्रीनहाउस गैंसे (Greenhouse Gases): पृथ्वी के वायुमंडल के भीतर सूरज की गर्मी को फँसाने वाली गैंसे, ग्रीनहाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं, जो दुनिया भर में खतरनाक रूप से तापमान बढ़ा सकती है। ग्रीनहाउस गैसों में ओज़ोन, मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लेरोफ्लोरो कार्बन (CFCs) शामिल हैं।

समुद्रीय अम्लीकरण (Ocean Acidification): वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढती मात्रा के कारण, पृथ्वी के समुद्रों के पी एच स्तर (pH Levels) में नियमित कमी आ रही है। जब समुद्र कार्बन डाईआकसाइड को अदंर लेता है, तब उसमे कई रासायनिक अभिक्रियाए पैदा होती हैं, जिनसे समुद्र के र्काबोनेट व केल्शम र्काबन पर्द्वाथ (Seawater Carbonate Ions and Calcium Carbon Minerals) कम हो जाते हैं। इन रासायनिक अभिक्रियाओं को समुद्रीय अम्लीकरण कहा जाता है। यह ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है कि समुद्रीय प्राणीयों का जिंदा रहना मुशकिल हो जाता है।

7.9 संदर्भ लेख

Calzadilla, A., Rehdanz, K., Betts, R., Falloon, P., Wiltshire, A., & Tol, R. S. (2013). Climate Change impacts on Global Agriculture. *Climatic Change*. 120 (1-2), 357-374.

Change, I. P. O. C. (2007). Climate Change 2007: The Physical Science Basis. *Agenda*. *6*(07), 333.

Costanza, R., & Patten, B. C. (1995). Defining and Predicting Sustainability. *Ecological Economics*. 15(3), 193-196.

Halvorssen, A. M. (2007). Common, but Differentiated Commitments in the Future Climate Change Regime-Amending the Kyoto Protocol to include Annex C and the Annex C Mitigation Fund. *Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y*.18, 247.

Harris, P. G. (1999). Common but Differentiated Responsibility: The Kyoto Protocol and United States Policy. *NYU Envtl. LJ*. *7*, 27.

Honkonen, T. (2009). *The Common but Differentiated Responsibility Principle in Multilateral Environmental Agreements: Regulatory and Policy Aspects* (Vol. 5). Kluwer Law International BV.

Jamieson, D. (1998). Sustainability and Beyond. *Ecological Economics*. 24(2-3), 183-192.

Nafziger, E. W. (2007). *From Seers to Sen: The Meaning of Economic Development. In Advancing Development.* London: Palgrave Macmillan.

Redclift, M. (1992). The Meaning of Sustainable Development. *Geoforum*. 23(3), 395-403.

Scoones, I. (2007). Sustainability. *Development in Practice*. 17(4-5), 589-596.

Stone, C. D. (2004). Common but Differentiated Responsibilities in International Law. *American Journal of International Law*. 276-301.

Tol, R. S. (2018). The Economic Impacts of Climate Change. *Review of Environmental Economics and Policy*. 12(1), 4-25.

Watson, R. T., Zinyowera, M. C., Moss, R. H., & Dokken, D. J. (1998). The Regional Impacts of Climate Change. Geneva: IPCC.

Weiss, E. B. (2002). Common but Differentiated Responsibilities in Perspective. In *Proceedings of the ASIL Annual Meeting*. Cambridge University Press.

World Bank. (2010). *World Development Report 2010: Development and Climate Change*. Retrieved from https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/4387

7.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

बोध प्रश्न 1

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**

- विकास का अर्थ मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करना, गरीबी, असमानता और बेरोजगारी को कम करना, जीवन स्तर को ऊपर उठाना, शिक्षा तक पहुँच में सुधार, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, आर्थिक और सामाजिक विकल्प का विस्तार करना है।
- विकास के कई तत्व है, उन्हें परिभाषित करना कठिन है। इसे लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है, आर्थिक और मानव विकास के संदर्भ में और सततता के संदर्भ में भी जाँचा जा सकता है।
- सततता एक प्रणाली, समुदाय, सामाजिक संस्थानों या सामाजिक कार्यों के समूह की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को संदर्भित करती है।
- सततता की अवधारणा किसी वस्तु की स्थिति या गुणवत्ता है, जो किसी अन्य चीज को सतत रखती है, उसकी रक्षा करती है, बनाए रखती है या संरक्षित कर सकती है।
- सतत विकास सततता प्राप्त करने की कुंजी है, जिसे अंतिम दीर्घकालिक लक्ष्य माना जाता है। दूसरे शब्दों में, सतत विकास का अर्थ है कि एक गतिविधि या प्रक्रिया को सतत रखना सुनिश्चित करता है कि एक प्रणाली दीर्घकालिक काम करती है।

2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**

- जलवायु परिवर्तन को स्थानीय, क्षेत्रीय या बड़े पैमाने पर परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो दीर्घकालिक औसत शासन के जलवायु को, तापमान, वर्षा परिसंचरण और संबंधित चर को दर्शाता है।
- मानव गतिविधियों के परिणामस्वरूप विशाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस (CO_2) उत्सर्जन हुआ है। यह ग्रीनहाउस गैसों का सबसे बड़ा स्रोत है, जो अपने वायुमंडल के भीतर पृथ्वी से अवरक्त विकरण को फंसा कर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पैदा कर सकता है।
- जलवायु परिवर्तन कृषि, वानिकी, ऊर्जा और तटीय क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों और उत्पादक वातावरण को प्रभावित करता है।

- यह स्थानीय औसत तापमान और चरम सीमाओं में वृद्धि की ओर जाता है, जैसे भूमि और पानी दोनों में वर्षा स्वरूप में परिवर्तन होता है। इसके आरंभ में, मौसमी वितरण और फिर यह चरम सीमा तक जाता है।
- यह बड़े तुफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की आवृति और तीव्रता को बढ़ाता है।

बोध प्रश्न 2

1. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**
   - आज पर्यावरण की समस्याओं को दूर करने के सभी वैश्विक प्रयास सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के सिद्धांत द्वारा संचालित होते हैं।
   - यह समर्थन करता है कि वैश्विक पर्यावरण विनाश के सामने सभी राज्य जिम्मेदार हैं, फिर भी समान रूप से जिम्मेदार नहीं है।
   - विभिन्न स्तरों को स्थापित करने की आवश्यकता है जिस पर विभिन्न राज्य अपनी क्षमता और समस्या में योगदान के स्तर दोनों के अनुसार प्रभावी रूप से एक सामूहिक प्रतिक्रिया में प्रवेश कर सकते हैं।
2. **आपके उत्तर में निम्नलिखित बाते शामिल होनी चाहियेः**
   - विकास, सततता और जलवायु परिवर्तन के बीच विविध संबंध विद्यमान है। कई देशों में ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव सतत विकास को रोक रहा है या यहाँ तक कि मौजूदा का विकास लाभ को नष्ट कर रहा है।
   - आज, वास्तविक चुनौती अन्य सामाजिक आकांक्षाओं को पूरा करते हुए पर्यावरणीय प्रदर्शन में आकस्मिक रूप से सुधार करना है।
   - प्रतिस्पर्धी मांगों को पूरा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति दोषपूर्णता को कम करने के लिए, समाजों को इन संसाधनों की रक्षा करने के साथ अपने प्राकृतिक संसाधनों से अधिक उत्पादन को संतुलित करने की आवश्यकता होगी।
   - पर्यावरण की सततता महत्वपूर्ण है।